RNI No. MPHIN/2018/76422

प्रेरणा स्त्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

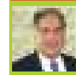

लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते।

रतन टाटा

वर्ष-03, अंक - 13 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 31 दिसम्बर 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

आरटीआई में निर्वाचन कार्य में घोटाले का हुआ खुलासा

राज्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को कार्रवाई के लिए की शिकायत

माही की गूंज, झाबुआ।

विधानसभा 2018 में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से विभिन्न मदों की राशि निर्वाचन स्थल पोलिंग बूथों पर खर्च करने के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर लेखन कार्य, परिवहन व्यवस्था, यात्रा भत्ता, राशन का मूल्य, भोजन व्यय, टेंट, बिजली, पानी आदि के लिए झाबुआ जिले की 973 पोलिंग बूथों पर तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सक्सेना, संबंधित शाखा प्रभारी प्रकाश सिंगाडिया द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप मालवीय ने लगाए है। सूचना अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार, जिले में विधानसभा 2018 के चुनाव में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवेदन देते हुए बताया कि, जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी झाबुआ द्वारा कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ को आदेश जारी किया था कि, संबंधित निर्वाचन 2018 विधानसभा चुनाव के लिए जिले की 973 पोलिंग बूथों पर समस्त व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषदों को व्यवस्था के लिए आदेश जारी करें। जिला पंचायत झाबुआ के पत्र क्रमांक 2824 16 नवम्बर 2018 को आदेश जारी किए गए थे, जिसमें समस्त पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद द्वारा ही अपने व्यव से सारी व्यवस्थाएं करनी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से मिलने वाली राशि कई मदों में जिले की 973 पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद को नहीं दी गई। जिले की 377 ग्राम पंचायत सहित थांदला, पेटलावद, मेघनगर जिसकी जानकारी आना बाकी हैं एवं झाबुआ तथा राणापुर के द्वारा ही उनके मद की राशि से समस्त बूथों पर खर्च होने वाली राशि का खर्च किया गया। झाबुआ जिले में विधानसभा 2018 के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से राशन, भोजन व्यवस्था करने के लिए जिले की 973 पोलिंग बूथों पर लगभग 24 लाख 32 हजार 500 रुपए देना थे, यानी प्रत्येक बूथ पर 2 हजार 500 रूपए देने थे। लेकिन उक्त रूपया नही देने के बावजुद भी पोलिंग बूथों पर 18 लाख 86 हजार 609 रुपए का फर्जी व्यव

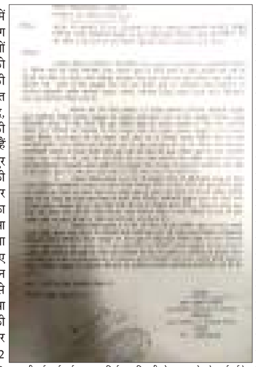

आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा राज्य निर्वाचन अधिकारी को मय दस्तावेज के कार्रवाई के लिए दिए की गई शिकायत की प्रतिलिपी।

निर्वाचन अधिकारी झाबुआ द्वारा बता दिया गया। साहब ने समस्त बूथ पर यह राशि जारी करना बताया, वहीं बचत राशि 5 लाख 85 हजार 891 रुपए बताया, जबकि जिले की 377 ग्राम पंचायतों सहित 5 नगर परिषदों के द्वारा ही 973 पोलिंग बूथों पर खुद के मद से राशि खर्च की गई। जिले के 973 पोलिंग बूथों पर प्रचार-प्रसार, रंगाई-पुताई, लेखन कार्य, लाइट, टेंट, बिजली, पानी आदि कई मदों की राशि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से जिला निर्वाचन शाखा झाबुआ को प्राप्त हुई थी, किंतु 973 पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद द्वारा उनके मद से ही खर्च किए गए निर्वाचन शाखा झाबुआ से ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषदों को कोई भी राशि नहीं आवंटित की गई। यह जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जिला कलेक्टर झाबुआ को छोड़कर की जावे एवं इसकी जानकारी आरटीआई ऐक्टीवीटीज को भी दी जाए की शिकायत जनहीत में आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को की।

दिए प्रमाणित दस्तावेज

आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिए गए आवेंदन के साथ सूचना अधिकार से प्राप्त जानकारी के प्रमाणित दस्तावेज भी दिए गए, जिससे निर्वाचन कार्य के लिए दी गई राशि मे बड़े भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है।

क्या होगी कार्रवाई ?

आरटीआई में निर्वाचन के नाम पर हुए बड़े खुलासे के बाद अब इस बात पर संशय है कि, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की जांच होगी या नही ? क्योंकि भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल में कई बड़े अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। निर्वाचन कार्य के दौरान ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होने की कसमें खिलाने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार करने में पीछे नही रहे। मामला सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की भी नीद उड़ी हुई है, क्योंकि इस तरह से पूरे प्रदेश में राशि का आवंटन किया गया था, अब ये जांच का विषय है कि, केवल झाबुआ जिले में निर्वाचन कार्य की राशि में भ्रष्टाचार हुआ है या पूरे प्रदेश भर में ये ही हालत है।

अलविदा 20-20 स्वागत 2021

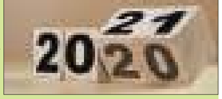

माही की गूंज, झाबुआ।

कोविड-19 के संक्रमण की आहट के साथ हुआ 20-20 अपने आप में कई अनोखी यादें छोड़कर जा रहा है, महामारी के प्रकोप से कई लोगों ने अपने प्रिय जनों को इनमें खोया, तो कई लोगों को अमीट दर्द भी यह वर्ष दे गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष मिर्श्रीत ही रहा, वर्ष के जाते-जाते बिहार चुनाव में जहां एक और एनडीए सरकार की वापसी जरूर हुई लेकिन जदयू को नुकसान और भाजपा को बढ़त हासिल हुई, वही वर्ष के प्रारंभ से मध्यप्रदेश में हुई हलचल मार्च तक कांग्रेस सरकार के पतन के पश्चात बंद हुई और वर्ष के जाते-जाते मध्यप्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत का कमल खिल गया।

हाऊडी मोदी कार्यक्रम एक जहां मोदी की ख्याति में चार चांद लगा गया, वही इस एतिहासिक कार्यक्रम के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ड्रंप सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। यह वर्ष देश को कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना गया। 22 मार्च को ऐतिहासिक जनता कर्फ्यू के बाद देश ने इतिहास में पहली बार इतनी लंबी अवधी का लॉकडाउन देखा, जो कई चरणों में लगाया गया। इस दौरान पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर आह्वान को सर आंखों पर लिया, फिर चाहे वह 22 मार्च को थाली और ताली हो या अप्रैल में दीपक जलाना हो, यही नहीं साल के अंत तक आते-आते प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को भी पूरी गंभीरता से लिया। लॉकडाउन में जहां पूरे देश में ताला लग चुका था, वही प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के लिए भी आम जनता ने पुरी दिलेरी दिखाई और हर संभव लोगों की मदद की, वहीं सरकार ने भी मजदूरों का दर्द समझते हुए स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से आम लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया। वहीं लॉकडाउन में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी कई राहत भरी घोषणाएं की, जिसमें नवंबर में मुफ्त अनाज के साथ ही गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 3 माह तक नगद राशि, साथ ही अन्य जरूरी सेवाओं के लिए भी राहत की घोषणा की गई।

मध्यप्रदेश में भी राजनीतिक दृष्टिकोण से यह वर्ष ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 22 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में न केवल विधायक पद से बल्कि कांग्रेस से भी त्यागपत्र दिया और एक साथ भाजपा में शामिल हुए, जिसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। इन विधायकों ने उप चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा और भाजपा सरकार आरामदायक बहुमत हासिल कर पाई।

जिले की राजनीति में इस वर्ष कोई विशेष हलचल नहीं हुई, जिले के तीनों विधायक वर्ष के प्रारंभ में जहां सत्ता पक्ष के थे वे अब विपक्ष के हो गए। झाबुआ विधायक व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र विक्रांत भूरिया का युवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना जरूर जिले के लिए गौरव की बात रही, वहीं भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन का दौर इस वर्ष में साबित हुआ। जिला अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण सिंह नायक की नियुक्ति हुई वही सत्ता परिवर्तन के बाद सांसद गुमान सिंह डामोर राजनीतिक रूप से अधिक शक्तिशाली साबित हुए पर उन्होने गुटबाजी के बिच अपना स्वयंभु गुट बनाकर जिले में गुटबाजी के साथ आपसी मन मुटाव को बढावा दिया।

वर्ष के अंत आते-आते जिले की सभी मंडलों की कार्यकारिणी घोषित हुई, वही मंडल परीक्षण भी आयोजित किए गए, पर इसी बिच जिले की भाजपा गुटबाजी के बिच भाजपाईयो का चरित्र भी सामने आया। वर्ष के अंत तक आते-आते कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी भारत सहित पूरे विश्व में हलचल मचा दी है, उम्मीद करते हैं कि 2020 जैसा बिता सौ बिता लेकिन आने वाला वर्ष सभी के लिए सुख समृद्धि व खुशहाली लाने वाला हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा 2020।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों पर आज फैसला ले सकती है सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार चार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले और पांच न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायधीश बनाने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों पर आज फैसला कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कागजी कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है और 31 दिसंबर तक फैसला आ सकता है।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने हाल में सरकार से आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने सहित चार मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 6 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उनकी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

ब्रिटेन से आने-जाने वाले विमानों पर 7 जनवरी तक रोक

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिटेन वाले कोरोना वायरस से भारत में भी हड़कंप मच गया है। 20 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने ब्रिटेन आने-जाने वाले विमानों पर रोक को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी कि, कोरोना वायरस के फैलते नए स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन से आने-जाने वाले विमानों पर रोक को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि, नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि, वायरस के ज्यादा संक्रामक नए स्वरूप के सामने आने की वजह से ब्रिटेन एवं भारत के बीच विमानों की आवाजाही 23 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक स्थगित रहेगी।

सरकार का बडा फैसला, बनेंगे दो बड़े ट्रेड कॉरिडोर

तीन लाख को मिलेगा रोजगार, योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, 7 हजार 7 सौ 25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने कृष्णपत्तनम और तुमाकुरू में औद्योगिक गलियारा और ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्र को मंजूरी दी है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2 हजार 139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

ट्रेड कॉरिडोर में होंगी सभी परिवहन सुविधाएं

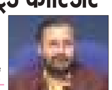

जावड़ेकर ने बताया कि, दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी। जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं, ऐसी जगहों पर औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का कार्य करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि, ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों को ऐसे देशों में भेजा गया जहां पिछले 70 वर्षों में कोई मंत्री नहीं गया हो। इसमें देशों के साथ संबंधों को मजबुत बनाने की भावना रही है।

मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र किया घोषित, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत नागालैंड को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, केंद्र सरकार का मत है कि, संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

अधिसूचना में कहा गया है कि, चूंकि नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है इसलिए संपूर्ण राज्य को 30 दिसंबर से छह माह तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। सरकार ने इसके लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की संख्या 28 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को आधार बनाया है।

सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता, केंद्र ने कहा- रद नहीं होगा कृषि कानून

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफपिछले एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत राजधानी के विज्ञान भवन में हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। बैठक शुरू होने से पहले वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि, हमें उम्मीद है कि, वार्ता निर्णायक होगी। हालांकि, इस वार्ता के नतीजों को लेकर संशय है। वहीं सरकार कह चुकी है कि इन कानूनों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उन्हें रद नहीं किया जाएगा।

कृषि कानून के मुद्दे पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच बातचीत के लिए बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठन पहुंचे हैं। सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में शामिल हुए। किसान संगठनों ने मांग की तीनों कानून वापस होने चाहिए।

किसान नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग की

किसान भवन में भोजन के लिए ले जाते एक कार सेवा टेम्पो को विज्ञान भवन में देखा गया। केंद्र और किसान यूनियनों के बीच फार्म कानूनों पर सातवें दौर की बातचीत हुई।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने विज्ञान भवन में दोपहर के भोजन के दौरान किसान नेताओं के साथ लंच किया। मंत्रियों ने लंगर ग्रहण किया।

सूत्रों के अनुसार, किसान नेताओं के साथ बैठक में केंद्र ने कहा, रद नहीं होगा कृषि कानून, केंद्र ने किसान नेताओं से पहले आंदोलन खत्म करने के लिए कहा। एमएसपी पर भी कहा कि, वे उस पर आगे बात कर सकते हैं।

चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से कहा कि, तीन कृषि कानूनों के बारे में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है।

गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किए बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। साल 2020 में कोरोना का खतरा पूरी दुनिया पर तो छाया ही रहा और अब इस खतरे की वजह से ही गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। हर साल 26 जनवरी को राजपथ पर मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की परेड की लंबाई कम कर दी गई है, इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है।

इस मामले में एक सूत्र ने बताया कि, इस साल गणतंत्र दिवस पर 25 हजार से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, आमतौर पर यह संख्या 1 लाख होती है। इतना ही नहीं 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी परेड देखने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।

कमल नाथ के निर्देश- प्रत्याशी चयन समिति समय से पहले नाम तय करे

नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने सर्वे फॉर्मूले को नकारा

छोटे शहरों में बड़ी जीत की उम्मीद

कमल नाथ के निर्देश पर उज्जैन घटना की जांच करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

यूपीए नेतृत्व को लेकर शिवसेना का फिर कांग्रेस पर तंज, बड़ी पार्टी होने पर खड़े किए सवाल

बड़ी पार्टी को दी शुभकामनाएं

संप्रग शासन में मनमोहन, पवार कृषि सुधारों के पक्ष में थे : नरेंद्र

11 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

नीतीश 'एक्शन रिप्ले' के मोड में, क्या हैं इसके सियासी मायने?

बिहार चुनाव के दौरान सियासी गलियारों में बिहार में का बा... की धूम थी। तब इंजन की सरकार बनने के महज 50 दिन के भीतर ही सुर, ताल व गति बदल गई है। बिहार से लेकर दिल्ली की सियासी गलियारों तक अटकलें लग रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है क्या। सब सवाल... अब आगे का क्या। क्या नीतीश 'एक्शन रिप्ले' के मोड में हैं। ऐसी नौबत क्यों आई?

मंदिर के दानपात्र का ताले तोड़ चोर चोरी कर हुए रफूचक्कर

माही की गूंज, रतलाम/ताल। तहसील मुख्यालय से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर रतलाम जिले का प्रसिद्ध मनुनिया महादेव मंदिर के दानपात्र के ताले तोड़ कर चोरों ने दो पेटियों पर लाखों की चोरी कर अपना हाथ साफकिया, चोरों ने चोरी की वारदात को रात 1 बजे अंजाम दिया। वही मंदिर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हुई पर फुटेज इतने साफ नहीं दिख रहे हैं कि, पुलिस चोरों को पहचान सके फिर भी ताल थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने फुटेज के आधार पर एवं पेटियों के ताले टूटे हुए के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ताल थाना टीआई अमित सारस्वत ने कहा कि, बहुत जल्दी चोर हमारे गिरफ्त में होगा ज्यादा दिन चोर अपनी खुशियां नहीं मना सकेगा।

101 युवाओ ने किया रक्तदान

माही की गूंज, रतलाम। वर्तमान समय मे जहा ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी को महसूस किया जा रहा है रक्त की कमी के कारण कई मरीजो को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है उसी दौरान बड़ावदा सेवा समिति ने जागरूकता दिखाते हुए रक्तदान शिविर आयोजीत किया जिसमें 101 युवाओं ने आगे आकर उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में रतलाम जिला चिकित्सालय की रक्तकोष की टीम को बुलाया गया, शिविर का प्रारंभ उज्जैन जिला ग्राम भारती अध्यक्ष रामेश्वर सेकवाड़िया द्वारा भगवान की पूजा-अर्चना कर किया गया। रक्तदान शिविर में सेदरी के युवाओं के साथ-साथ बड़ावदा सेवा समिति, राष्ट्रवादी युवा किसान संगठन, मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार विरोधी फोरम के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दुर्घटना में हुई थी बेटे की मौत, बेटे की याद में पिता ने बनवाया हॉस्पिटल

माही की गूंज, रतलाम।

अपनों की याद में आपने लोगो को कई स्मारक बनाते तो जरूर देखे होंगे, वही रतलाम में एक पिता ने अपने दिवंगत बेटे की याद में एक छोटा अस्पताल बनाकर ही गांव को भेट कर दिया, ताकि दूसरो की जान बचाई जा सके। 10 बिस्तरों वाला यह छोटा अस्पताल है जिसकी चर्चा जोरो पर है।

गम की चोटें जख्मो पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी और मां-बाप की दौलत, दुनिया में बेटे से बढ़कर क्या होगी। मां की आँखों में आंसू, चेहरे पर बेटे के खोने का दर्द व पिता के मन में दिवंगत बेटे की यादें, लेकिन इन सभी बातो को पीछे छोड़कर इस पिता ने समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि लोगो के जहन में इनके दिवंगत बेटे की यादें अमर हो गई।

रतलाम के धराड़ गांव के रहने वाले पाटीदार दंपति पेशे से किसान है, जिन्होंने अपने बेटे की याद में गांव को 10 बिस्तरों वाला अस्पताल का एक वार्ड ही बनाकर सौप दिया, धराड़ गांव के हेमेंद्र पाटीदार ने अपने बेटे शिवम की याद में उसकी पुण्यतिथि पर अपने गांव को यह सौगात दी है। 2018 में हुए एक सड़क हादसे में शिवम् की मौत हो गई थी, गांव में प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। पिता ने अपने बेटे को अपने आखों के सामने मरता देखा तो प्रण किया की आगे से किसी भी पिता के साथ ऐसा ना हो इसलिए 10 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाकर गावं को सौपकर अपने आप में एक मिसाल कायम की है।

हाजरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपने वाहन में बैठकर करती है टाइम पास

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उप संचालक भोपाल की डॉक्टर पुत्री की मनमानी

महिला डॉक्टर के अभाव में परेशान होती महिला मरीज

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

ड्यूटी टाइम पर कार में बैठी डॉक्टर कल्पना भकोरिया और कैमरा देख कर कार से बहार आकर बहस करती डॉक्टर भकोरिया।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे विकास खण्ड के अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अपनी ड्यूटी लापरवाही से कर रहे है, जिससे लोगो को स्वास्थ्य सुविधाए समय पर नही मिल पा रही है, खास कर महिला डॉक्टर के कारण शासकीय अस्पताल में पहुंचने वाली महिला वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद में भी ऐसा मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग में बड़े पद पर पदस्थ अपने पिता के दम पर महिला चिकित्सक अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले रोगियों का इलाज करने की बजाए, अपने निजी वाहन में बैठकर टाइम पास कर ड्यूटी का दिखावा कर रवाना हो जाती है।

डॉक्टर कल्पना भकोरिया नही करती इलाज, उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर बैठती है निजी वाहन में

उप संचालक भोपाल डॉक्टर भकोरिया की डॉक्टर पुत्री अपने पिता के पद ओर रुतबे का फायदा उठाते हुए मनमानी करने पर उतारू है, डॉक्टर कल्पना भकोरिया रोज स्वास्थ्य केंद्र तो ड्यूटी बजाने मनमाने समय पर आती है और उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर कुछ देर अपने चेम्बर में बैठकर वापस अस्पताल परिसर में खड़े अपने निजी वाहन में बैठ जाती है और लंच होने का इंतजार करती है जैसे ही लंच का समय होता है डॉक्टर मेडम रवाना हो जाती है और वापस ड्यूटी पर नही लौटती।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की कमी है एक और अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर उर्मिला चोयल अपनी निजी प्रेक्टिस और निजी हॉस्पिटल पर ज्यादा इलाज करती है तो दूसरी महिला डॉक्टर ड्यूटी टाइम पर अपनी कार में बैठी रहती है जिससे अस्पताल में आने वाली महिला मरीजों को कई बार अपनी गम्भीर समस्या को लेकर पुरूष डॉक्टरो के पास जाना पड़ता है।

मीडिया में मामला आने के बाद जोइन की ड्यूटी

डॉक्टर कल्पना भकोरिया लम्बे समय से पेटलावद में पदस्थ है, लेकिन वो ड्यूटी पर नही आती थी और वेतन ले रही थी, जिसका मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद डॉक्टर कल्पना को ड्यूटी जोइन करने आना पड़ा, लेकिन ड्यूटी जोइन करने के बाद भी अस्पताल में अपनी ड्यूटी के साथ न्याय नही कर पा रही है और खानापूर्ति के लिए हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का शासकीय ड्यूटी टाइम सुबह 9 बजे से डेढ़ बजे और दोपहर ढाई बजे से 4 बजे का है, लेकिन मेडम न तो टाइम से आती है और हाजरी लगाकर कुछ देर में ही वाहन में जाकर बैठती है और दूसरी शिफ्ट से पहले ही घर रवाना होकर कई बार वापस ही नही लौटती।

अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से भी हो जाएगा खुलासा

मामले की जानकारी मिलने के बाद दो-तीन बार अस्पताल परिसर में इसकी पुष्टि के लिए वीडियो बनाने हम अस्पताल परिसर पहुंचे जहा मेडम अपने निजी वाहन में बैठी मिली, मीडिया का कैमरा देख डॉक्टर साहिबा अपने वाहन में से उतर कर वीडियो बनाने पर सवाल करने लगी और खुद को वाहन में बैठने के सवाल पर कार में पानी पीने के लिए आने की बात कहने लगी। हमारे पास मेडम के ड्यूटी टाइम पर कार में बैठे रहने की अलग-अलग दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है और विभाग के जिम्मेदार चाहे तो अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और ओपीडी से दवाई की पर्ची के रिकॉर्ड की जांच कर पुष्टि कर सकते है कि, मेडम अपनी ड्यूटी कैसे बजा रही है।

प्रभावी पिता के कारण नही होती कार्रवाई

डॉक्टर कल्पना भकोरिया के पिता स्वास्थ्य विभाग भोपाल में एड्स विभाग के उप संचालक के पद पर बैठे है, जिनके प्रभाव के कारण मेडम मनमानी करने में लगी हुई है और अधिकारी भी सब कुछ जान कर अंजान बने हुए है, जब विभाग के जिम्मेदारो से इस विषय मे बात की तो मामूली गलतियों पर नोटिस देकर कार्रवाई करने वाले अधिकारी केवल मामले को दिखवाने की बात कर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते है।

चन्द्र शेखर आजाद स्टेडियम खेल मैदान में जमा पानी, खिलाड़ी परेशान

माही की गूंज, कुशलगढ़। नितिन झाकरोद

कुशलगढ नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण नगर के एकमात्र खेल मैदान चन्द्र शेखर आजाद स्टेडियम में गन्दा पानी जमा होने से प्रेक्टिस के लिए आने वाले बच्चो ओर खिलाड़ीयो को परेशान होना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा स्टेडियम से पहले गंदे पानी की निकासी का नाला अधूरा छोड़ देने से और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करने से खेल मैदान के बाहर और अंदर गंदे पानी का तालाब बन गया है।

गंदा पानी जमा होने से मैदान में खिलाड़ियों को खेलने लायक जगह नहीं बची है, दिन-प्रतिदिन पानी बढ़ने से समस्या बढ़ती ही जा रही है। चार दिवारी के समीप गंदा पानी जमा होने से दो वर्ष पूर्व लाखों की लागत से बनी चार दिवारी को भी नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते खेल मैदान में कीचड़ व गंदगी फैलने से यहां खेलने आने वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि, गांव के बच्चों को खेलने के लिए मैदान की साफ-सफाई व सुरक्षा के लिए कदम उठाए ताकि कस्बे का एकमात्र खेल मैदान सुरक्षित रहे।

भाजपा नेता अजय जैन ने लोक निर्माण विभाग मंत्री से मुलाकात कर पुलिया निर्माण की रखी मांग

11 माह से टूटे पड़े पुल से रायपुरिया-झाबुआ मार्ग पर राहगीर हो रहे परेशान

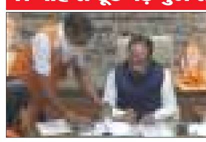

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद तहसील को झाबुआ जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क रायपुरिया झाबुआ मार्ग की पुलिया विगत 11 माह से टूटी हुई हैं, जिसको लेकर मीडिया द्वारा मामला प्रमुखता से उठाया था। मामले में भाजपा नेता अजय जैन द्वारा पेटलावद पीडब्लूडी एसडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उक्त मामले और आमजन की परेशानी को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात कर पुलिया निर्माण कार्य शीघ्र करवाने की बात कही थी, मंगलवार को भाजपा नेता अजय जैन ने भोपाल पहुँच कर लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात कर पुलिया निर्माण की मांग रखी, साथ ही पुल के 11 माह से टूटे होने के कारण आमजन और वाहन चालकों को हो रही परेशान की सभी प्रमुख अखबार में प्रकाशित खबरें को भी आवेंदन के साथ पेश कर हो रही दिक्कतों से अवगत करवाया, भाजपा नेता अजय जैन ने बताया कि, मंत्री महोदय ने आमजन की समस्या को देखते हुए तुरंत फाइल प्रमुख सचिव की और भेज दी है, उम्मीद है जल्द ही पुल निर्माण संबधी कार्रवाई पूरी हो जाएगी।

एसडीओ लक्ष्मी गामड़ को हटाए जाने की मांग

भाजपा नेता अजय जैन ने विभाग की एसडीओ लक्ष्मी गामड़ पर भी गंभीर आरोप लगा कर उनको भी हटाए जाने की मांग की है। जैन ने बताया कि, समाचार पत्रो में खबरे आए दिन छप रही है लेकिन एसडीओ ने आज तक इस बाबद कोई ठोस कदम नही उठाए गए हैं, एव कांग्रेस शासन में कांग्रेस के लोगो की पसंद की अधिकारी होने से भाजपा शासन में निष्क्रिय हैं तथा जनहित की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है, पेटलावद एसडीओ का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाना चाहिए की बात कही।

रतलाम-झाबुआ मार्ग के लिए भी रखी मांग

प्रदेश के कई बड़े शहरो सहित प्रदेश की सीमा से लगे राज्य को जोड़ने वाला प्रमुख झाबुआ-रतलाम मार्ग की खस्ता हालत को देखते हुए उक्त मार्ग के पुनः निर्माण करने की मांग भी मंत्री गोपाल भार्गव के समक्ष रखी है।

मौसम की मार और नीलगाय के आतंक से किसान परेशान, फसल की हो रही बर्बादी

माही की गूंज, रतलाम/नवेली। राघवेंद्र सिंह डोडिया

कृषि प्रधान देश में समूचे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला अन्नदाता किसान आए दिन प्रकृति के प्रकोप से दो-चार हाथ करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर 2 जून की रोटी, शादी ब्याह या अन्य जीवन यापन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए अपने खून को पसीने में बदल कर हाड़ जलाने वाली कड़ाके की ठंड में रात भर पानी मे खड़ा रहकर फसल को अपने बच्चे की तरह परवरिश करके, बड़ा करता है ओर फिर अतिवृष्टि, सूखा या अन्य आपदाओं से त्रस्त हो कर भी हिम्मत नही हारते हुए, फिर से डट कर खड़ा रहता है। क्यों कि ये समस्या हमेशा या निरन्तर क्रम में नही आती या रहती है, परन्तु ,वर्तमान समय मे क्षेत्रीय किसान अन्नदाता रोज घोड़ा (नीलगाय) नामक एक ऐसी आपदा, विपदा,का शिकार हो रहा है जो कृषकवर्ग के लिए निरन्तर आपदा, विपदा,के रूप में विकराल रूप में समस्या बनकर क्षेत्र में उभर रही है। समस्या भी ऐसी की जिसका कोई स्थाई समाधान ही नही नजर आता दिख रहा है, किसान रात दिन कर अपनी फसल को अपने गाड़ी कमाई लगाकर बड़ी करने में लगा हुआ है, लेकिन रोज घोड़ो (निलगाय) के झुंड किसान की लहलहाती फसल को कुछ ही घंटों-मिनटों में चौपट करके रख देते है। वर्तमान में रोज घोड़ो के लिए 3 से 5 फिट तक की तार फेंसिंग, बाड़ या बागर कोई मायने नही रखती है, यह 4 से 5 फिट तक की फेंसिंग को लांग कर आसानी से आ जाते है, रोज घोड़ो के झुंड से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

रोज घोड़े बडी संख्या में रतलाम जिले के पीपलोदा, नवेली, कालूखेड़ा, सुखेड़ा, जावरा, आलोट, बाजना, रावटी, लगभग समूचे क्षेत्रो में है, ओर ज्यादा तादाद में होने के कारण यह दिन ओर रात के समय अचानक सड़क पर भी आ जाते है, जिसके कारण क्षेत्र में कई सड़क हादसे भी होते रहते है। इस समस्या को लेकर कई बार किसानों ने वन विभाग व स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया है, परन्तु वन विभाग या प्रशासन के पास भी इसका स्थाई समाधान या कोई युक्ति नजर नही आ रही है।

एमपी का डकैत सज्जनगढ़ में चुरा रहा था मवेशी, हुआ गिरफ्तार

ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए आरोपी पर लूट, डकैती, नकब जनी के काकनवानी थाने में पुर्व से 8 केस दर्ज

माही की गूंज कुशलगढ़ (राज.)। सज्जनगढ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार घरों से बाहर बंधे पशु चोरी हो रहे थे। परेशान ग्रामीणो ने कई बार पुलिस को शिकायत की इस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए ग्राम रक्षकों का दल बनाया, इसके साथ ही गश्ती भी बढ़ा दी। इसके बाद ही 26 दिसंबर को तड़के साढे 3 बजे सज्जनगढ की ग्राम पंचायत नालपाड़ा में एक घर के आंगन में बंदी बकरी चुराने का प्रयास हुआ। लेकिन ग्रामीणों ने आरोपी को घेर लिया, सूचना पर चौकी प्रभारी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद का नाम मध्यप्रदेश के देवका निवासी शैतान पुत्र नाथू सिंघाड़ा बताया साथ ही चोरियां करना कबूल किया। थाना अधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि, जब आरोपी का रिकॉर्ड पता किया तो उसके खिलाफकाकनवानी थाने में लूट, नकबजनी, और डकैती के 8 केस दर्ज है। थाना अधिकारी ने बताया कि, आरोपी से पूछताछ में जिले की अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। वहीं पुलिस पूछताछ में यह पता कर रही है कि, आरोपी ने चोरी किए हुए मवेशियों का क्या किया।

संपादकीय

किसानों आंदोलन का गतिरोध तोड़ना मोदी सरकार के लिए जरूरी

भारत में कृषि की औसत विकास दर 4 फीसदी से भी कम है। यह औसत तब है, जब जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के गेहूं और धान पड़े हैं। वह अनाज सड़ भी रहा है। उसके बावजूद हर साल पंजाब और हरियाणा से गेहूं और धान की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती रही है। सवाल है कि क्या खेती गेहूं और धान तक ही सीमित है? फल, सब्जी, नकदी फसलें, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन और ऑर्गेनिक खेती आदि में जुटे छोटे और सीमांत किसानों की चिंता कौन करेगा? गेहूं और धान की जरूरत देश में खाद्य संकट समाप्त होने के साथ ही कम होती जा रही है। कृषि अर्थशास्त्रियों का भी सवाल है कि एमएसपी पर सरकारी खरीद उन इलाकों में कब शुरू की जाएगी, जो अभी तक उपेक्षित, गरीब और विपन्न रहे हैं? आजादी के 73 साल बाद भी हमें 70 फीसदी से ज्यादा खाद्य तेल आयात क्यों करना पड़ता है?

किसान आंदोलन की बुनियादी चिंता और उसके सरोकार इन सवालों पर केंद्रित होने चाहिए थे, लेकिन ये मुद्दे गायब रहे हैं। सिर्फ एमएसपी और कानूनों की वापसी का ही शोर सुनाई देता रहा है। भारत सरकार आश्वासन देती रही है और किसान संगठन उसे खारिज करते रहे हैं। इस गतिरोध और विरोधाभास को देखते हुए एक महीना बीत चुका है। अभी तक आंदोलन के मायने समझ से परे हैं। बेशक सरकार कटघरे में है और उससे असंख्य सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन आंदोलन अधूरा और एकांगी-सा क्यों लगता रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के किसानों को संबोधित किया, तो वामपंथी दलों और कांग्रेस पर बेहद तीखे प्रहार किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उनकी हठधर्मिता के कारण वहां के 70 लाख से ज्यादा किसान सम्मान-निधि से वंचित रहे हैं। बंगाल पर 34 साल तक शासन करने वाले वामपंथियों और कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दे पर आंदोलन की आवाज नहीं उठाई। क्या बंगाल के किसान इस आर्थिक मदद के पात्र नहीं हैं? यहीं प्रधानमंत्री ने भी गंभीर आरोप लगाया कि बंगाल को बर्बाद करने वाले अब उठकर पंजाब आ गए हैं और किसानों को भड़का रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के सार्वजनिक आरोप को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। इन आरोपों से पहले भी ये शंका जताई जा रही थी कि किसान आंदोलन किन्हीं और हाथों में खेल रहा है, लिहाजा हर संवाद नाकाम रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को प्रस्ताव और अपना एजेंडा भेजा है और 29 दिसंबर को 11 बजे बैठक बुलाने का आग्रह किया है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल अपनी जगह हैं कि क्या समझौते के कोई आसार हैं? अथवा सरकार किसानों के एजेंडे को स्वीकार कर सकती है?

अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की छवि उभर रही थी, लेकिन पहली बार वह कमजोर और भ्रमित लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कच्छ, रायसेन (मप्र), सुशासन दिवस पर, जम्मू-कश्मीर में किसानों समेत देश को संबोधित किया है। रविवार को 'मन की बात' भी साझा की है। बीच में सिखों के गुरु तेगबहादुर के 'शहादत दिवस' पर रकाबगंज गुरुद्वारे भी गए और मत्था टेका। तमाम कोशिशों के बावजूद आंदोलित किसान इंच भर भी न तो पीछे हटे हैं और न ही सरकार के साथ समझौते के मूड में हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों की फसलें एमएसपी पर ही बिकतीं, तो उन्हें करीब 2000 करोड़ रुपए का फायदा होता, लेकिन किसान को सरकार से जो सबसिडी मिलती है, वह ऊंट के मुंह में जीरा समान है। भारत में प्रति किसान 20,000 रुपए सालाना से भी कम सबसिडी दी जाती है, जबकि अमरीका में यही सबसिडी 42 लाख रुपए से अधिक है। सरकार कह सकती है कि अमरीका की अर्थव्यवस्था से तुलना नहीं की जा सकती। बहरहाल प्रधानमंत्री इतना तो आश्वासन दे सकते थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन मीडिया के जरिए किसानों की जो सोच सामने आती है, उससे स्पष्ट है कि उन्हें प्रधानमंत्री के कथन पर भी यकीन नहीं है। तो बेहद गंभीर सवाल है कि गतिरोध कैसे टूटेगा और प्रधानमंत्री देश के करोड़ों किसानों को भरोसा दिला पाएंगे?

थाली पीटने भर से मंगलमय नहीं होगा नया साल

थाली पीटने भर से मंगलमय नहीं होगा नया साल

सियाराम पांडेय श्शांतश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष के अंत में अपने मन की आखिरी बात की। उनकी मन की बात का दिल्ली सीमा पर आंदोलित किसानों ने थाली बजाकर विरोध किया। तर्क दिया कि मोदी जी ने कहा था कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। हम थाली इसलिए बजा रहे हैं कि कृषि कानून भाग जाए और हमारा नववर्ष मंगलमय हो जाए। सवाल उठता है कि किसानों को कानून चाहिए या नहीं। अपनी बात मनवाने के लिए वे पूरे एक माह से आंदोलन कर रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहकर चले जाते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते। उनके समर्थक नेता भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि उनके मन की बात सुनी जाए। लोग अपने तरीके से अपने मन की बात करते भी हैं। इस देश का हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता हो लेकिन उसके सुने जाने की अपनी सीमा होती है। बात सब सुनें, इसके लिए पात्रता तो जरूरी होती ही है, बात में दम भी होना चाहिए। इस बात को कदाचित कोई समझना नहीं चाहता। तिस पर शिकायत यह कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। तर्क और तथ्य के आईने में कही गई बात ही संसार गौर करता है।

प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी को सबके मन की बात सुननी चाहिए। यह उनका धर्म भी है और दायित्व भी। अगर वे हर माह अपने मन की बात कहकर इस देश की जनता का मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ नवोन्मेष करने की बात करते हैं। कौशल प्रशिक्षण और अपने में काबिलियत पैदा करने की सलाह देते हैं तो इसमें गलत क्या है? भारतीय संस्कृति में ताली तब बजाई जाती है जब किसी का अभिवादन करना हो, किसी को शाबासी देनी हो। थाली तब बजाई जाती है जब परिवार में कोई मंगल अवसर उपस्थित हुआ हो लेकिन यहां विरोध की थाली बज रही है, यह बात समझ से परे है। जो लोग अपने हित के लिए देश के हितों को ताक पर रख रहे हैं। टोल नाका फ्री कराए बैठे हैं, वे देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, शायद इसकी उन्हें कल्पना नहीं।

रही बात कानून की तो वह व्यक्ति के काम करने और रहन-सहन की सीमा निर्धारित करता है। उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, यह तय करता है। कानून कुछ नहीं, व्यक्ति की जीवनशैली का नियमन है। व्यक्ति खुद नियंत्रित हो जाए तो उसे पुलिस और अदालत की वैसे भी कोई जरूरत नहीं होती लेकिन जब देश का हर आदमी ऐसा करेगा तभी इसकी अहमियत है। वर्ना जो कुछ भी होगा, वह किसी बुरे सपने और भयावह मंजर से कम नहीं होगा।

कानून के साथ एक सच यह भी है कि वह किसी व्यक्ति को स्वच्छंद नहीं रहने देता। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो बंदिशों को पसंद करता हो। सबकी एक ही कोशिश होती है कि उसपर किसी का नियंत्रण न रहे। 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई' वाली भावभूमि ही सबको अच्छी लगती है लेकिन अगर कानून न हो, संविधान न हो, जीवन जीने की कोई आचार संहिता न हो तो क्या होगा? बेहद अराजक माहौल सृजित हो जाएगा। सब अपने-अपने हित पर आमादा हो जाएंगे और संसार से शांति का नामोनिशान मिट जाएगा। सबको केवल 'अपना कहा, अपना किया' ही अच्छा लगेगा। लोग एक-दूसरे के हितों पर भारी पड़ने लगेंगे।

मन की बात तो सभी कहना चाहते हैं लेकिन कह कितने लोग पाते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मन की बात को कहना बहुत आसान नहीं है। मन हमेशा सुख की ही अनुभूति करे, ऐसा मुमकिन तो नहीं। सुख-दुख दोनों भाई हैं। दोनों के स्वभाव और प्रभाव अलग-अलग हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यूं समझें कि एक पेट है और दूसरा पीठ है। पेट-पीठ को जैसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सुख-दुख को भी व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता।

अधिकांश लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। संविधान खतरे में है लेकिन किसके चलते तो सबका एक ही जवाब होगा कि सरकार के चलते। सरकार किसने बनाई, इस तरफ कोई सोचता नहीं। सरकार जब आपने बनाई है तो सरकार के काम के लिए उत्तरदायी कौन है, इसका जवाब कौन देगा? जनता को सरकार से परेशानी है तो सरकार नाम की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। संविधान से परेशानी है तो संविधान खत्म कर दिया जाए। पुलिस-प्रशासन से परेशानी है तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। ऐसे में बचेगा क्या? जनता और उसकी स्वच्छंदता। जनता का मतलब व्यक्ति और उसकी गतिविधियां। जब कोई काम का मूल्यांकन करने वाला ही नहीं होगा तो कौन किसकी बात मानेगा? यह अपने आप में बड़ा किंतु जटिल सवाल है और इसका जवाब आम जनमानस की ओर से आना ही चाहिए।

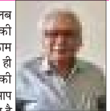

सियाराम पांडेय 'शांत'

प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वे देश में बनाए सामानों का ही इस्तेमाल करें जिससे देश के कारीगरों को, उत्पादकों को लाभ हो। कुछ लोगों का तर्क है कि वे सरकार से बात भी करेंगे और मानेंगे भी नहीं। यह तो वही बात हुई कि 'पंचों की राय सिर माथे लेकिन खूंटा नहीं उखड़ेगा।' ऐसी वार्ता का कोई मतलब नहीं है। सरकार को लगता है कि उसने अच्छा कानून बनाया है और देश के अधिकांश किसानों, बुद्धिजीवियों को लगता है कि पहली बार किसानों के लिए कुछ विशेष हुआ है, लेकिन मुट्ठी भर किसान ऐसे हैं जो इस बहाने सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक दल भी नीम पर करेले की तरह चढ़ गए हैं। वे दरअसल बात बनने नहीं दे रहे हैं।

किसान नेता यह तो चाहते हैं कि उनका नववर्ष मंगलमय हो लेकिन वे नए कृषि कानूनों को हटवाकर ही दम लेना चाहते हैं। सरकार की समस्या यह है कि वह एकबार झुकी तो राजनीतिक दल उसे सही ढंग से काम नहीं करने देंगे। छोटी-छोटी समस्या लेकर लोग सड़कों पर उतरने लगेंगे। इन कानूनों को खत्म करने का मतलब है, बड़े आढ़तियों और बड़े व्यापारियों की दुरभिसंधि का सफल होना। इससे देश मजबूत नहीं होगा, वरन कमजोर ही होगा। थाली और ताली पीटने से नहीं, अपने और देश के बारे में सोचने और तदनुरूप काम करने से ही किसानों का नववर्ष मंगलमय होगा। उनका भी और देश का भी।

किसान गुत्थीः कुछ सुझाव

सरकार और किसान नेताओं के बीच अब जो बातचीत होने वाली है, मुझे लगता है कि यह आखिरी बातचीत होगी। या तो सारा मामला हल हो जाएगा या फिर यह दोनों तरफ से तूल पकड़ेगा। धरना देने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान काफी दमदार, मालदार और समझदार हैं और सरकार भी अपनी ओर से किसानों का गुस्सा मोल नहीं ले सकती है। 60-70 करोड़ लोगों को कुपित करने वाली सरकार को दो-चार अडानी-अंबानी नहीं बचा सकते। सरकार उनसे नोट तो ले सकती है लेकिन वे इसे वोट कहां से ला कर देंगे? इसीलिए 30 दिसंबर की इस वार्ता को सफल होना ही चाहिए। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। दोनों पक्ष उन पर विचार कर सकते हैं।

पहला, खेती मूलतः राज्यों का विषय है। संविधान की धारा 246 में यह स्पष्ट कहा गया है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को (पंजाब, हरियाणा आदि) छूट क्यों नहीं दे देती ? जिन राज्यों को ये तीनों कानून लागू करना हो, वे करें, जिन्हें न करना हो, वे न करें। वे खुद तय करें कि उनका फायदा किसमें हैं? दूसरा, देश के 94 प्रतिशत किसान एमएसपी की दया पर निर्भर नहीं हैं। केंद्र सरकार चाहे तो सिर्फ 23 चीजों के ही क्यों, केरल सरकार की तरह दर्जनों अनाजों, फलों और सब्जियों के भी न्यूनतम मूल्य घोषित कर सकती है। उन्हें वह खरीदे ही यह जरुरी नहीं है। इसीलिए इन कृषि-कानूनों की जरुरत ही क्या है ?

तीसरा, किसान अपना माल खुले बाजार में खुद बेचते हैं। उन्हें इन सरकारी कानूनों से कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ये किसान अपनी खेती और जमीन अभी भी ठेके पर देने के लिए मुक्त हैं। ये कानून बनाकर सरकार फिजूल का सिरदर्द क्यों मोल ले रही हैं?

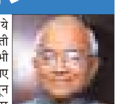

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

चौथा, उपज के भंडारण की सीमा हटाना ठीक नहीं मालूम पड़ता है। इससे बड़े पूंजीपतियों को लूटपाट की खुली छूट देने का शक पैदा होता है। भंडारण की सीमा लगाने का अधिकार सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिए। पांचवाँ, यदि कृषि-कानूनों को सरकार अपनी इज्जत का सवाल बनाए बैठी है तो इन छह प्रतिशत मालदार किसानों की टक्कर में वह 94 प्रतिशत छोटे किसानों के समानांतर धरने देश में जगह-जगह क्यों नहीं आयोजित कर सकती है ? जरा करके दिखाए !

चाणक्य नीति

जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते है वो तो बच्चों के शत्रु के सामान हैं। क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किये जाते हैं जैसे हंसो की सभा मे बगुले।

राजनीतिक हिंसा सभ्य समाज के लिए खतरनाक

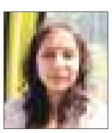

सोनम लववंशी

पश्चिम बंगाल में यूं तो चुनाव आगामी साल में होना है। लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ रही है। एक ओर तो सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जमीन तैयार करने में लगे है। तो दूसरी और आये दिनों हिंसा की घटनाएं भी बंगाल में बढ़ती जा रही है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अपना पुराना इतिहास रहा है। लेकिन अब ये हिंसा तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन बचाने में लगी है तो वही भाजपा अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने की जद्दोजहद में लगी है। ऐसे में कहीं न कहीं यही विस्तारवाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सियासत में उथल पुथल का कारण बन गयी है। वैसे पश्चिम बंगाल में रक्त रंजिश का अपना पुराना इतिहास रहा है। जिसकी शुरुआत लार्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुई थी। इसके बाद से ही बंगाल में हिंसा का दौर बद्दस्तूर जारी है। गौर करने वाली बात तो यह है कि चुनावी हिंसा में कोई एक दल शामिल नही है। बल्कि समय समय पर सभी दलों पर यह आरोप लग चुके है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के शासन काल में तो चुनावी रंजिश में हुई हत्या इतिहास के पन्नो में दर्ज है। 1977 से 1996 तक 28 हजार लोग राजनीतिक हिंसा की बलि चढ़ चुके है। राजनीतिक हिंसा का यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2018 में सबसे अधिक राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई। भारत मे 54 राजनीतिक हत्या में अकेले 12 बंगाल में हुई। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1999 और 2016 के बीच 18 सालों में हर साल करीब 20 राजनीतिक हत्या हुई। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय का चुनाव हो हिंसा के बिना बंगाल के चुनाव की राजनीति नही होती है। भाजपा बंगाल फ्तह करने की राह में आगे बढ़ रही है। तो वही ममता के किले की दीवारें खुद उनकी अपनी पार्टी के नेता ढहाने में कोई कोर कसर नही छोड़ रहे है।

दीदी पर इस समय दोहरा संकट मंडरा रहा है। एक ओर तो उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे है तो वही उनकी पार्टी के नेता उनका दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे है। ऐसे में हिंसा बढ़ना स्वभाविक बात है।

बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। जो बंगाल अपनी प्रतिभा, कला, संगीत, सिनेमा , साहित्य से विश्व भर में विख्यात था आज वही बंगाल रक्त रंजिश राजनीति के कारण विश्व भर में बदनाम हो रहा है। बंगाल की राजनीतिक हिंसा आए दिनों मीडिया रिपोर्ट की सुर्खियां बन रही है। क्या यह वही बंगाल है जिसकी माटी में महाप्रभु चौतन्य, रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के विचार विश्व को नई दिशा और दशा प्रदान करते थे। आज उसी बंगाल में राजनीति के नाम पर खूनी खेल का नाच हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों के अपने वैचारिक मतभेद होते है, लेकिन यह मतभेद बंगाल में हिंसा के रूप में प्रकट होते है। अफ्सोस कि जिस बंगाल ने ष्सुजलाम सुफ्लाम शस्यश्यामलाष् के संगीत से देश का मान बढ़ाया हो। आज उसी बंगाल में माटी मानुष की लड़ाई खूनी संघर्ष का रूप ले चुकी है।

बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसी पर हिंसा और हत्या के आरोप लगते है। बंगला में एक कहावत है - जेई जाए लंका, सेई होए रावण इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भी लंका जाता है, वही रावण बन जाता है। बंगाल की राजनीति में यह कहावत एक दम सटीक बैठती है जो भी बंगाल की राजनीति में सत्ता पर काबिज होता है, वह अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए हिंसा का रूप अख्तियार कर ही लेता है। अब यह तो समय ही बताएगा कि बंगाल की राजनीति में किसके माथे ताज सजता है और कौन सत्ता से बेदखल होता है। चुनाव आते आते बंगाल की राजनीति की तस्वीर क्या रूप दिखाएगी यह आने वाला समय ही बताएगा। इन सब के बीच कहीं न कहीं राजनीतिक हिंसा एक संवैधानिक देश के लिए उचित नहीं। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नही होना चाहिए। ऐसे में अगर समाज और देश को राह दिखाने वाले लोग ही हिंसा की राह अख्तियार कर लेंगे फिर सामाजिक स्थिति पिछड़ेपन का शिकार तो होगी ही साथ ही कानून व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। इसलिए बेहतर व्यवस्था के निर्माण पर जोर देना सियासतदां का कर्तव्य बनना चाहिए न कि व्यवस्था को चौपट करना।

कोरोना से बाहर निकलती आर्थिकी

केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए कामकाज के नियमों को आसान बना दिया है। इससे इन कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की जगह वर्क फ्रॉम एनिवेयर (कहीं से भी काम) को बढ़ावा मिलेगा। ये उद्योग लंबे समय से सरकार से नियमों में बदलाव की मांग कर रहे थे। केंद्र ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और आईटी आधारित सेवाएं प्रदाता कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों को अब सरल कर दिया है। इससे उद्योग का अनुपालन बोझ कम होगा। साथ ही वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर को बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों से सेवा प्रदाताओं के लिए 'घर से काम' और 'कहीं से भी काम' के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। ऐसी कंपनियों के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग और अन्य सेवा शर्तों को भी समाप्त कर दिया गया है। आईटी उद्योग 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर लंबे समय से राहत दिए जाने की मांग कर रहा था और इसे स्थायी आधार पर जारी रखने की मांग कर रहा था। आज भी देश के अनेक संस्थानों ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का ऐलान कर रखा है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने लोगों को घर से काम करने का मौका दिया था। इस नए कल्चर को शुरुआत में सभी द्वारा स्वीकार कर पाना मुश्किल था। संस्थानों और कर्मचारी वर्ग दोनों को वर्क फ्रॉम होम के लिए काफ्ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन की लंबी अवधि ने धीरे-धीरे उनको इसकी आदत डाल दी। दिलचस्प बात यह है कि अब लोग वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को इतना पसंद करने लगे हैं कि वापस ऑफिस जाकर काम नहीं करना चाहते। इसके लिए वे अपनी सैलरी से भी समझौता करने को तैयार हैं।

वर्क फ्रॉम होम के इस कल्चर से फायदा भी और नुकसान भी हुआ। साल 2020 के जून और जुलाई के महीने में करीब 1000 लोगों पर किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से हर तीन में से एक कर्मचारी ने हर महीने कम से कम तीन हजार से पांच हजार तक की बचत की है। साथ ही इससे ऑफिस आने-जाने, बाहर खाने-पीने और कपड़ों वगैरह का खर्चा बचा है। यही कारण है कि करीब 74 फीसदी लोग अब घर से ही काम करना पसंद कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी अधिकतर निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम को जारी रखा है। कुछ मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि घर से काम करने से सिर्फ कर्मचारियों को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे कंपनी की कार्यक्षमता को बढ़ाने की संभावनाएं भी नजर आई हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में घर से काम करने से कर्मचारियों के ट्रैवलिंग और मीटिंग के दौरान फिजूल में खर्च होने वाले समय की बचत हुई है। अब इस समय का उपयोग वे कंपनी की किसी अन्य योजना को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ेगी, साथ ही कर्मचारियों की ग्रोथ भी होगी। वर्क फ्रॉम होम की वजह से सुबह से सड़कों पर लगने वाले जाम में भी कमी आई है। अगर इसे आगे जारी रखा जाता है तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होने से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट संभव हो सकती है। आम तौर पर वर्क फ्रॉम होम के फायदे ही फायदे नजर आते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ऑफिस जाने वाले व्यक्तियों के आठ घंटे ऑफिस के होते हैं, लेकिन जब वह घर वापस आते हैं तो अपना समय परिवार को देते हैं। वहीं जो लोग घर से काम करते हैं, वे भले ही पूरा दिन परिवार के साथ हों, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं होते। सोते-जागते उन्हें अपने कमिटमेंट पूरे करने की चिंता लगी रहती है। इसके कारण कभी-कभी उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

जो लोग घर से काम करते हैं, उनके काम का एक रेट तय होता है और चाहकर भी व्यक्ति उन्हें बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकता। दरअसल घर से काम करने पर आप ऑफिस में बॉस से लगातार संपर्क में नहीं रहते। केवल फोन या ईमेल के जरिए ही काम होता है। कभी-कभी तो कम्युनिकेशन के अभाव में काम भी प्रभावित होता है। साथ ही कम्युनिकेशन गैप के चलते लोग जल्द आपको नोटिस नहीं करते और न ही आप अपने भीतर के गुणों को उनके समक्ष रख पाते हैं। ऐसे में प्रमोशन होना या काम के रेट में वृद्धि होना काफी मुश्किल होता है। वर्क फ्रॉम होम के चलते डिजिटल चौनल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के चलते साइबर क्रिमिनल्स भी काफी सक्रिय हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ टिप्स हैं। उदाहरण के तौर पर डिवाइसेज और ऑनलाइन अकाउंट्स के सभी डिफॉल्ट पासवर्ड बदल दें। इसके बाद मजबूत पासवर्ड रखें। मीटिंग लिंक्स को सार्वजनिक तौर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर न करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफिस के कोलेबोरेटिव वर्क के लिए उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करें जो भरोसेमंद हों या फिर आपके नियोक्ता मुहैया कराए हों। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटी वायरस और ऐप्लिकेशन्स के अपडेटेड वर्जन का इस्तेमाल करें। किसी ओपन या फ्री वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करने से बचें। अपने घर के वाई-फाई और एडमिन के डिफॉल्ट पासवर्ड बदल दें। आपकी ईमेल आईडी पर आने वाले किसी भी फिशिंग ईमेल से बचें। इन ईमेल में भेजे जाने वाले लिंक मैलिशियस हो सकते हैं। इन पर क्लिक करने से पहले ध्यान से जांच लें। ऑफिस सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो, रिमोट एक्सेस को डिसेबल रखें। अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ करें। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑफिस के काम और एंटरटेनमेंट के लिए एक ही डिवाइस का इस्तेमाल न करें।

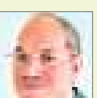

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
विख्यात अर्थशास्त्री

जहां तक संभव हो, अपनी कंपनी से मिले कंप्यूटर तथा लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें और पर्सनल सिस्टम पर ऑफिस का काम करने से बचें। वर्क फ्रॉम होम के दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। गलत पोजीशन में घंटों लैपटॉप पर काम करने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं। इस दौरान लोगों में रीढ़ का दर्द, सर्वाइकल, पीठ दर्द, कंधे में दर्द जैसी परेशानियां सामने आई हैं। लगातार कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर काम करने के कारण आंखों में जलन और पानी आने तथा नींद न आने जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। इसके बावजूद कौन नहीं चाहता है कि वह अपनी मर्जी का मालिक बने। घर बैठे पैसे कमाए। कई करोड़ शहरी भारतीय आज भी यही सपना देखते हैं। स्वरोजगार के लिए वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा क्षेत्र है। फ्रीलांसर इनकम्स अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में वर्क फ्रॉम होम के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह वर्ष वर्क फ्रॉम होम की कल्चर में अधिकता के लिए भी याद रखा जाएगा। वर्क फ्रॉम होम से स्वरोजगार प्राप्त करने वाले अपने देश में अनेक शख्स ऐसे भी हैं जिनके आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर होने के निरंतर प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राणवायु मिल रही है।

स्वस्थ्य प्रजातंत्र की मुख्यधारा

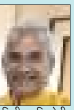
डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। अलगाववाद का दशकों पुराना अध्याय धूमिल हो रहा है। उसकी जगह मुख्यधारा का प्रभाव है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी इसका प्रमाण है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश को भी लाभान्वित करने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। यह चिकित्सा सुविधा मात्र नहीं है। बल्कि आयुष की सर्वे सन्तु निरामयः की कामना भी है।

इस प्रदेश के लोगों ने अलगाववादी अनुच्छेद 370 की समाप्ति को अपना पूरा समर्थन दिया है। इस मसले पर चर्चा के दौरान देश को दिलचस्प पहलू की जानकारी हुई। बताया गया कि यह अनुच्छेद केवल दो तीन राजनीतिक कुनबों को ही भरपूर लाभ पहुंचा रहा था। आमजन को तो इससे नुकसान ही हो रहा था। यह सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही है। उन्हीं दो-तीन कुनबों के नुमाइंदे स्वयं को बेनकाब कर रहे हैं। ये लोग चीन और पाकिस्तान के सामने फरियाद कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन मुल्क भी घिसे-पिटे मोहरों पर दांव नहीं लगाते। लेकिन इस हरकत से इनकी हकीकत सामने आ गई। ये लोग अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए क्यों इतने बेकरार है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ किया। यह जन आरोग्य योजना सरकार की ओर से पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती होने वाले हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का कवर मिलता है। इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्य कर सकते हैं। प्रशासन स्थानीय परिवारों के नाम भी अब अपने डेटाबेस में छूटे हुए नाम जोड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को देशभर के चौबीस हजार से अधिक अस्पतालों में पोर्टेबिलिटी के तहत बीमा की सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पहले आदेश दिया था। यही लोग केंद्र सरकार को प्रजातंत्र की नसीहत दे रहे है। केंद्र सरकार गांवों तक विकास पहुंचा रही है। योजना से लेकर अमल और देखरेख तक पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। गरीब से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब पंचायतों का दायित्व महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची, यहां के गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं।

कोरोना काल में भी जम्मू-कश्मीर में करीब अट्ठारह लाख सिलेंडर रिफिल कराए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर में दस लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए। जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक सुधार के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हुए। इसको लेकर आशंका व्यक्त की जा रही थी। अलगाववादी गुपकर ने पहले इसके बहिष्कार का आह्वान किया था। बाद में जनता का मिजाज देखकर चुनाव में उतरे। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। केसर की घाटी में कमल खिला है। भाजपा यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिला विकास परिषदों के चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर वासियों ने लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया है। चुनावों में भाजपा के चौहत्तर, नेशनल कांफ्रेंस के सड़सठ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ताईस और कांग्रेस के छब्बीस उम्मीदवार विजयी रहे। यह विरोधियों के लिए सबक है। लेकिन वह अब भी गलतफहमी में हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने गुपकर घोषणा के पक्ष में मतदान किया है। जिससे साबित हो गया है कि गुपकार गठबंधन केवल कश्मीर पर आधारित राजनीतिक पार्टी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने अनुच्छेद-370 को हटाने के फैसले को नामंजूर कर दिया है।

श्रीनगर की खानमोह से भाजपा विजेता ऐजाज हुसैन की जीत उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि यह मोदी जी की नीतियों की जीत है। जनता ने दुष्प्रचार को नकार दिया है। लोग विकास की नीतियों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह जीत साबित करती है कि भाजपा आने वाले समय में विकास को आगे ले जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जम्मू-कश्मीर में संपन्न हुए डीडीसी चुनाव आशा की जीत हैं। जम्मू-कश्मीर में जम्हूरियत नयी अँगड़ाई ले रहा है। पहले वहां हाथ में पत्थर देखे जाते थे लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वहां बैलेट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि गुपकार गठबंधन इसलिए बना था क्योंकि भाजपा से इस गठबंधन के दल अकेले नहीं लड़ सकते थे। इसके बावजूद भाजपा को इतने मत मिले जो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के संयुक्त मतों से ज्यादा है। दो वर्ष पहले हुए पंचायत चुनावों के बाद पहली बार केन्द्र से पंचायतों के पास पैसा पहुंचने लगा था। इससे विकास के काम हुए जिसे जनता ने महसूस किया। जनता ने राज करने वालों और काज करने वालों के बीच अंतर को समझा है। लोगों ने सालों बाद केन्द्र का पैसा गांवों तक पहुंचते देखा है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भारतीय ज्ञान परम्परा और भाषा को बंधक से छुड़ाने का अवसर

गिरीश्वर मिश्र

पिछले दिनों काशी में देव दीपावली के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को, जिसे तस्करी में चुराकर एक सदी पहले कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के संग्रहालय को पहुंचा दिया गया था, बंधक से छुड़ाकर देश को वापस सौंपे जाने की चर्चा की थी। तब वहां के कुलपति टामस चेज ने बड़ी मार्के की बात कही थी कि 'यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जाय और उपनिवेशवाद के दौर में दूसरे देशों की विरासत को जो नुकसान पहुंचा है, उसे ठीक करने की हरसंभव कोशिश हो।'

आशा की जाती है कि इस साल के अंत होते-होते यह मूर्ति अपने मूल स्थान पर पुनरू विराजित हो जाएगी। दरअसल विपन्नता की स्थिति में अपनी बहुमूल्य संपत्ति को गिरवी रखना और स्थिति सुधरने पर उसे छुड़ाकर वापस लाना कोई नई बात नहीं है और इसका दस्तूर अभी भी जारी है। भारत की समृद्ध ज्ञान संपदा और उसकी अभिव्यक्ति को भी इतिहास के एक बिन्दु पर अंग्रेजों के पास बंधक रख दिया गया। पर परेशानी यह है कि उसकी एवज में जो लिया गया या मिला, उसकी परिधि में ही शिक्षा का आयोजन हुआ और अभ्यासवश उसके मोहक भ्रम में हम कुछ ऐसे गाफिल हुए कि अपनी संपदा को अपनाना तो दूर उसे पहचानने से भी इनकार करते रहे। महान मैकाले साहब ने जो तजबीज भारत के लिए की, उसे हमने कुछ इस तरह आत्मसात कर लिया कि स्मृति-भ्रंश जैसा होने लगा और विकल्पहीन होते गए। इसके चलते अपने स्वभाव के अनुसार सोचने-विचारने पर कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगा कि कोल्हू के बैल की भाँति पीढ़ी-दर-पीढ़ी हम पराई दृष्टि के पीछे ही चलते रहे। चलने से गति का अहसास तो हो रहा था पर दृष्टि पर पड़े आवरण से दिशा-बोध जाता रहा। इसका परिणाम सामने है। आईआईएम और आईआईटी की शिक्षा के कुछ सुरम्य द्वीप के चारों ओर कुशिक्षा का समुद्र हिलोरें ले रहा है। आज डिग्रीशुदा बेरोजगारों की संख्या, गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर शिक्षा और भारत के स्वभाव और संस्कृति से बढ़ते अपरिचय के बीच शिक्षा जगत में बेचैनी व्याप्त है।

प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकन जरूर बढ़ा और संस्थाओं की संख्या भी बढ़ी पर उनमें पढाई-लिखाई का स्तर कमतर होता गया और सबकुछ जटिल होता गया। आज प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का प्रवेश हो जाना, जग जीतने का कारनामा जैसा हो गया है। इस स्तर पर जितनी विषमता व्याप्त है उसका अनुमान लगाना भी कठिन है।

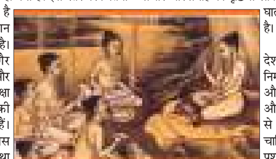

सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और उनके वर्ग भेद 'शिक्षा के अधिकार' की धज्जियां उड़ाते हैं। उसकी ऊंची फीस और व्यवस्था अभिभावकों के लिए तनाव का बड़ा कारण बन रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का हाल यह है कि दर्जा पांच का बच्चा दर्जा दो के स्तर का ज्ञान नहीं रखता और उसकी बुनियादी जानकारी को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन की बात कही गई है।

इस बात से शायद ही किसी कि असहमति हो कि शिक्षा और ज्ञान की थोपी हुई शिक्षा की दृष्टि अंग्रेजों की औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति का उपाय थी न कि यहाँ की अपनी जैविक उपज। यह बात संदेह से परे है कि अंग्रेजों ने भारत को अपने लिए आर्थिक स्रोत के रूप में लिया और यथासंभव शोषण और दोहन किया। उनकी विश्व दृष्टि के परिणाम देश को स्वतंत्रता मिलने के समय साक्षरता, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में व्याप्त घोर विसंगतियों में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता का अवसर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने का अवसर था परन्तु राजनैतिक स्वराज के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन का विवेक कठिन सिद्ध हुआ। फलतः स्वाधीन होने पर भी देश का शासन तंत्र, उसके हाव-भाव और लक्ष्य में अंग्रेजी दौर की निरंतरता भी व्यापक रूप से कायम रही। उदासीनता, अज्ञान और आलस्य के चलते जो कुछ जैसे चल रहा था चलता रहा। अंग्रेजी शिक्षा नीति ने समाज को सदा-सदा के लिए अनपढ़, ज्ञानी और विज्ञानी आदि की ऐसी कोटियाँ बना दीं जिसने कई नई जातियां खड़ी कर दीं और वर्चस्व की नई तस्वीर रच दी। ज्ञान तक पहुँच के बीच रोड़े दर रोड़े खड़े होते गए। आज सात दशक बाद भी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भारत की भाषा के लिए बंद है। भाषा और ज्ञान की दृष्टि से हम जिस तरह परनिर्भर होते गए वह ज्ञान के प्रचार और प्रवाह की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है।

शिक्षा का उद्देश्य देश के मानस का निर्माण करना होता है और वह देश-काल और शिक्षा संस्कृति से विलग नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस प्रश्न को छेड़ने से हम बचते-बचाते रहे और भारत की समझ की भारतीय दृष्टि की संभावना के प्रति संवेदनहीन बने रहे। राजा बदलने के बावजूद व्यवहार के स्तर पर राजकाज में बहुत कुछ लगभग वैसा ही बना रहा। संभवतः औपनिवेशक दृष्टि की औपनिवेशिकता ही दृष्टि से ओझल हो गई और उसकी अस्वाभाविकता भी बहुतों के लिए सहज स्वीकार्य हो गई, मानों मात्र वही संभव हो। ज्ञान का केंद्र पश्चिम हो गया और उसी का पोषण और परिवर्धन औपचारिक शिक्षा का ध्येय बन गया। इस कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा को भी अबाध रूप से प्रश्रय दिया गया। इसके सामाजिक-सांस्कृतिक आशय से बेखबर हम उसी मॉडल को आगे बढ़ाते गए और बिना जांचे-परखे भारतीय ज्ञान परम्परा को हाशिए पर धकेलते गए।

भाषा, जो ज्ञान का प्रमुख माध्यम है, वह ज्ञान का पैमाना बन गया। शिक्षा में स्वराज्य एक स्वप्न बनता गया। अंग्रेजी उन्नति की सीढ़ी बन गई। जो अंग्रेजी जाने वही कुलीन, पंडित और योग्य करार दिया जाने लगा। सामाजिक भेदभाव और सामाजिक दूरी ही नहीं स्वास्थ्य, कानून और न्याय आदि से जुड़े नागरिक जीवन की सामान्य सहूलियतें भी इससे जुड़ गईं। बारह-पन्द्रह प्रतिशत लोगों की अंग्रेजी अस्सी प्रतिशत से अधिक भारतीय जनों की भाषाओं पर भारी पड़ रही है। इस बाध्यता के चलते पढ़ाई-लिखाई और अध्ययन-अनुसंधान परोपजीवी होता चला गया। मौलिकता और सृजनात्मकता की जगह अनुकरण, पुनरुत्पादन और पिष्ट-पेषण की जो प्रबल धारा प्रवाहित हुई उसने जिस घोर अन्धानुकरण को बढ़ावा दिया। उसने देश-काल और संस्कृति से काटने के साथ जिस दृष्टिकोण को स्थापित और संबर्धित किया उसके चलते हम बिना किसी द्वंद्व के उस यूरो-अमेरिकी नजरिए को सार्वभौमिक मान बैठे जो मूलतः सीमित, स्थानीय और एक खास तरह का 'देसी' ही था परन्तु आर्थिक-राजनैतिक तंत्र की बीच पश्चिम से निर्यात किया गया। यह कितना अनुदार रहा यह इस बात से प्रमाणित होता है कि इसने भारतीय ज्ञान परम्परा को अप्रासंगिक और अप्रामाणिक ठहराते हुए प्रवेश ही नहीं दिया गया या फिर उसे पुरातात्विक अवशेष की तरह जगह दी गई। उसका ज्ञान सृजन के साथ कोई सक्रिय रिश्ता नहीं बन सका।

मुश्किल यह भी हुई कि भारतीय ज्ञान धारा में भारत का जो थोड़ा बहुत प्रवेश हुआ भी वह उसका पाश्चात्य संस्करण था, जिसमें दुराग्रहपूर्ण और गलत व्याख्याएं भी शामिल थीं। दूसरी ओर भारतीय समाज को पश्चिमी सिद्धांतों की परीक्षा के लिए नमूना (सैम्पल) माना जाता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में हमने गांधीजी की सीख भुला दी कि हमें अपनी जमीन पर अपने पाँव जमकर टिकाए रखना है। हाँ , खिड़कियाँ जरूर खुली रखनी हैं ताकि बाहर की बयार आती जाती रहे। हम यह भी भूल गए कि शिक्षा को समग्र व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा होना चाहिए ताकि हाथ, दिल और दिमाग सभी कार्यरत रहें। हमें मानव सेवा में ईश्वर सेवा का भाव भी नहीं रहा और न मनुष्य के रूप में जीने के लिए जरूरी आत्म नियंत्रण का भाव ही रहा।

यह संतोष की बात है कि नई शिक्षा नीति गहनता से इन विसंगतियों से रूबरू होते हुए विषयगत, प्रक्रियागत और संरचनागत बदलाव की दिशा में अग्रसर हो रही है। बंधक पड़ी सरस्वती को भी छुड़ाना आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परम्परा और संस्कृत समेत सभी भारतीय भाषाओं को बड़े लम्बे समय से पराभव में रखा जाता रहा है। आशा है नई शिक्षा नीति उनके साथ न्याय कर सकेगी।

अंगदान: मृत्यु के बाद भी अमर हुआ जा सकता है

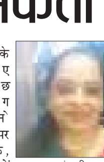
रंजना मिश्रा

अमर होने के लिए अब कठोर तपस्या या अमृत पीने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपने अंगों का दान करके मृत्यु के पश्चात भी अमर हुआ जा सकता है। डीएनए के रूप में अंगदान करने वाले व्यक्ति का अस्तित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। उस अंग में मौजूद डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता रहेगा। अगर उस व्यक्ति के अंग चार पांच लोगों को ट्रांसप्लांट हो गए तो यह अमरता और अधिक प्रबल हो जाएगी और वह उन सभी लोगों में अपने अंगों के रूप में जीवित रहेगा।

व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यादें और अच्छी बातें ही उसे संसार में जिंदा रखती हैं किंतु अंगदान करके वह कई लोगों को नया जीवन दे सकता है और उनमें अपने अंगों के जरिए जिंदा रह सकता है। इंसानी अंगों को बनाना अभी मुमकिन नहीं हुआ है, इस पर रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर से मिलते-जुलते कुछ अंग बनाने में उन्हें सफलता मिल सकती है किंतु इसमें अभी 5 से 10 वर्ष तक का समय लग सकता है इसलिए यदि किसी रोगी का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो ट्रांसप्लांट के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति का अंग लगाकर उसे स्वस्थ किया जा सकता है। हालांकि अभी भी लोग अंगदान करने से झिझकते हैं और इसलिए ट्रांसप्लांट के लिए अंगों का मिलना बहुत कठिन हो जाता है।

आंखों को छोड़कर बाकी अंगों का ट्रांसप्लांट तभी संभव है जब अंगदान करने वाले व्यक्ति के दिल की धड़कनें चलती रहें, भले ही उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया हो। जब शरीर के बाकी अंग काम कर रहे हों किंतु ब्रेन ने किसी वजह से काम करना बंद कर दिया हो और फिर से उसके काम करने की संभावना भी न हो तो व्यक्ति को ब्रेन डेड माना जाता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं जैसे सिर में गंभीर चोट लगना,

ट्यूमर या लकवे की वजह से।

ब्रेन डेथ और कोमा में फर्क है। कोमा से इंसान फिर से नॉर्मल हो सकता है किंतु ब्रेन डेथ होने के बाद ऐसा नहीं होता। कोमा की स्थिति में इंसान के दिमाग का कुछ हिस्सा काम कर रहा होता है, जबकि ब्रेनडेड में नहीं। इसलिए अंगदान ब्रेन डेड वाले मरीजों का ही हो सकता है कोमा के मरीजों का नहीं।

वैसे तो अंगदान किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही होता है पर ब्रेन डेड को मौत के बराबर ही माना जाता है। जीवित व्यक्ति दो में से अपनी एक किडनी का दान कर सकता है, लीवर का एक छोटा हिस्सा भी दान किया जा सकता है। मरने के बाद सबसे ज्यादा आंखों का दान किया जाता है। अंगदान करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, किंतु 18 साल से 65 साल तक की उम्र में अंगदान करना सबसे बेहतर होता है।

अंगदान करने से पहले कई चीजों की मैचिंग कराई जाती है। मसलन किडनी के मामले में एच एल ए, लीवर और हार्ट के मामले में ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराई जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी पॉजिटिव, सिफलिस और रैबीज जैसी बीमारियों से ग्रस्त मरीज अंगदान नहीं कर सकते।

अंगदान करने वाले ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर के अंगों को जितनी जल्दी हो सके निकालने की कोशिश की जाती है। अंग निकालने के 6 से 12 घंटों के अंदर ही ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए नहीं तो अंग ट्रांसप्लांट करने योग्य नहीं बचता।

लोग मृत्यु के बाद भी अमर रहना चाहते हैं। इसके लिए कुछ लोग अपने नाम पर सड़क, इमारतें और संस्थान बनवाते हैं। सार्वजनिक स्थानों या पार्क में प्रतिमा लगवाते हैं। पुराने जमाने में लोग अपने पूर्वजों के नाम पर धर्मशाला और मंदिर बनवाते थे। लोगों की चाहत होती है कि मृत्यु के बाद भी उनको याद रखा जाए। हालांकि अमर होने का सबसे बढ़िया तरीका अंगदान ही है।दुनिया में याद किए जाने के लिए एक लंबे जीवन की नहीं बल्कि प्रभावशाली जीवन जीने की आवश्यकता होती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

किसानों की आड़ में राजनीति या सरकार बनाम किसान

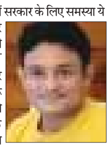
डॉ. शंकर सुवन सिंह

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।इस व्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है।मिश्रित अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है।किसान भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी है।किसान के बिना कृषि शब्द का कोई महत्व नहीं है।किसान और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं।कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।हाल ही में किसानो द्वारा भारत सरकार पर एम.एस.पी.(मिनिमम सपोर्ट प्राइस) पर कानून बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिसके चलते किसान आंदोलित है।सरकार एम.एस. पी .(न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानून बनाने को राजी नहीं है।सरकार किसानो को यह आश्वासन जरूर दे रही कि एम.एस.पी. खत्म नहीं होगा और किसानो की फसल सरकार एम.एस.पी. पर खरीदती रहेगी।सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे एम.एस.पी. कहा जाता है।एम.एस.पी.में सरकार की तरफसे गारंटी होती है की हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे।अगर मंडियों में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उनकी फसल एम.एस.पी. पर खरीद लेती है। इससे बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का किसानों पर असर नहीं पड़ता। स्वतंत्रता के बाद शुरूआती दशकों में किसानो की फसलों का अत्यधिक उत्पादन हो जाने पर उन्हें उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। फलस्वरूप किसान अपनी फसलों का वाजिब दाम पाने के लिए आंदोलन करने लगे।तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1 अगस्त 1964 को एल.के.झा. के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करना था ।समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए एम.एस.पी. का ऐलान किया गया।इसके बाद से हर साल सरकार बुवाई से पहले फसलों का एम. एस. पी. घोषित कर देती है। देश में एम.एस.पी. तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई, जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। यह अलग-अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। वहीं गन्ने का एम.एस.पी. तय करने की जिम्मेदारी गन्ना आयोग के पास होती है।एम. एस. पी. तय करने के बाद सरकार स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिये अनाज खरीदकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसी.आई.) और नेफेड(नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफइंडिया लिमिटेड) के पास उसका भंडारण करती है। फिर इन्हीं स्टोर्स से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के जरिये गरीबों तक सस्ते दामों में अनाज पहुंचाया जाता है।शुरुआत में केवल गेहूं के लिए एम.एस.पी. तय किया गया था। इससे किसान बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की फसल उगाने लगे, जिससे अनाजों का उत्पादन कम हो गया। फिर सरकार की तरफ से धान, तिलहन और दलहन की फसलों पर भी एम.एस.पी. दिया जाने लगा। फिलहाल धान, गेहूं, मक्का, जई, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमूखी, गन्ना, कपास, जूट समेत 20 से अधिक फसलों पर एम.एस.पी. दिया जाता है। फसलों की बुआई से पहले एम.एस.पी. तय की जाती है।जबकि कटाई के बाद प्रोक्योरमेंट घोषित किया जाता है। दरअसल साल 1968-69 के बाद से ही एम.एस.पी. और प्रोक्यरमेंट को एक जैसा समझा जाने लगा। प्रोक्योरमेंट के लिए अलग से कोई व्यवस्था नही की गई। एमएसपी को ही प्रोक्योरमेंट माना जाने लगा। आज किसान बिल आने के बाद शोर मचाया जा रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है लेकिन

1969 के बाद से ही एम.एस.पी. और प्रोक्योरमेंट को एक ही में मिला दिया गया। जिसके चलते हुआ है कि बुआई से पहले और कटाई के बाद जो फसल उगाने का खर्च बढ़ा उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। न पुरानी सरकार ने, न ही मौजूदा सरकार ने। प्रत्येक राजनैतिक पार्टी अपनी राजनीती चमकाने के लिए किसान बिल को आधार बना रही है।किसानो का मसला है और देश का असली किसान सरकार के पक्ष में है।सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाला हर व्यक्ति किसान नहीं है।किसानो की आड़ में राष्ट्र विरोधी तत्व भी अपना हाथ सेक लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ।एम.एस.पी और प्रोक्योरमेंट पुराना मसला है अतएव किसानो को भी चाहिए की आपसी सहमति का परिचय दें। देश का असली किसान अपने खेतों खलिहानो में है न की सड़को पे।जो किसान सड़क पर है उसको भी राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए न की राष्ट्र के विरोध में।किसान की बात सरकार मान ले तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ जाएगा। भारत सरकार को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी देखनी है।यंहा तो आंदोलित किसान और विपक्षी पार्टियां सिर्फऔर सिर्फअपना भला देख रहे हैं।किसानों से एम.एस.पी. पर खरीदे गए अनाज से सरकार सिर्फ पी.डी.एस.(सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में राशन बांटती है।बाजार में किसी अनाज की कमी होती है, तो सरकार अपने भंडार से अनाज जारी करती है। भंडारों में रखा सरकार का अधिकतर अनाज खराब हो रहा है।इसके बावजूद सरकार हर साल किसानों से अनाज खरीदती है जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी का कहना है, श्आज देश में इतना अनाज है कि देश में रखने की जगह नहीं है।किसान कहता है कि मेरे से ले लो, चाहे जहां फेंको।आज देश को दलहन और तिलहन की जरूरत है।इनका काफी आयात होता है। उनके लिए प्रोक्योर करके एम.एस.पी. क्यों नहीं करते हैं।क्या सिर्फगेहूं और चावल से आगे बढ़ना है हमें? सरकार भले ही 20 से ज्यादा फसलों के लिए एम.एस.पी. तय करती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी स्तर पर खरीद केवल गेहूं और धान की हो पाती है। ऐसे में सभी किसानों को एम.एस.पी. का फायदा नहीं मिल पाता। इसकी वजह यह है कि गेहूं और धान को सरकार पी.डी.एस. प्रणाली के तहत गरीबों को देती है इसलिए उसे इसकी जरूरत होती है। बाकी फसलों की उसे इतने बड़े स्तर पर जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनकी खरीद नहीं हो पाती।किसान बिल पर पर सबसे ज्यादा जोर पंजाब और हरियाणा के किसान का ही क्यों है? क्योंकि एम.एस.पी. का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। पंजाब के किसानों का 95: से ज्यादा अनाज तो एम.एस.पी पर बिक जाता है लेकिन बाकी देश के सिर्फ6: किसान ही अपना अनाज एम.एस.पी. पर बेच पाते हैं ।वहीं सरकार के लिए समस्या ये है कि अगर उसने सभी फसलें एम.एस.पी. पर खरीदनी शुरू कर दीं तो सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा।कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना का कहना है, श्23फसलों का पूरा प्रोडक्शन निकालते हैं और पूरा एमएसपी खरीदते हैं तो ये पूरा 15 लाख करोड़ होता है।जिस तरह से किसानों ने घेराबंदी कर दी है, अगर प्राइवेट सेक्टर भी कह दे कि हम नहीं खरीदेंगे तो सरकार क्या करेगी?व्यापारी वर्ग क्या करेगा?वो कहेगा हम बाजार से नहीं खरीदेंगे, सरकार से खरीदेंगे तो सरकार को 15 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।ऐसे में किसान खड़ा होगा और कहेगा कि मैं सब कुछ छोड़ कर वही उगाऊंगा जो सरकार खरीदेगी।ऐसा होने पर 30 लाख करोड़ रुपये का कृषि खरीद का बजट होगा और आपका टोटल रेवेन्यू 16 लाख करोड़ है तो क्या देश पर ताला लगवाना है?श्किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो उसका आंदोलन अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है।अतएव हम कह सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानो का आंदोलन अपरिपक्वता की निशानी है।

न्यूज ब्रीफ

इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा

माही की गूंज, खरगोन। पिछले तीन दिनों के मुकाबले बुधवार को ज्यादा ठंड होने से तापमान भी लुढ़क गया है, जो इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तहसील कार्यालय खरगोन स्थित मौसम वैद्यशाला से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। गत मंगलवार को खरगोन में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया था।

वाहन चलाने का प्रशिक्षण आईटीआई में दिया जाएगा

माही की गूंज, खरगोन। परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंदौर में नंदानगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) इंदौर में हल्के वाहन चालन का 30 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती बरखा गौड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम में 155 घंटों का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित है। अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस प्रशिक्षण के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इंदौर के बाहर से आने वाली महिलाओं के लिए छात्रावास एवं भोजन की निःशुल्क सुविधा आईटीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी है।

गलत मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने वाला सचिव निलम्बित

माही की गूंज, बड़वानी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋतुराजसिंह ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना का नियम विरूद्ध लाभ देने के लिए गलत मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने वाले ग्राम पंचायत बेडदा के पंचायत सचिव जुवानसिंह अलावे को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय पाटी नियत किया गया है।

आंगनवाडी केंद्रों पर होगा रियूसेबल कपड़े के नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण

माही की गूंज, खरगोन। कोविड-19 के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन में सैनेटरी नेपकिन की अनुपलब्धता होने से महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। शहरों में सैनेटरी नेपकिन का प्रयोग ज्यादा होता है। ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में सैनेटरी नेपकिन के उपयोग का प्रतिशत आर्थिक समस्या और जानकारी के अभाव में काफी कम आंका गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं और किशोरियों को स्थानीय स्तर पर रियूसेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। महिला बाल विकास संचालक श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि, 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल 17 हजार 5 आंगनवाडी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कपड़े के सुविधाजनक रियूसेबल सैनेटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण वॉटर-एड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाईन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में स्व-सहायता समूह की महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शामिल होंगी। श्रीमती नायक ने बताया कि, प्रशिक्षण में बनाए गए सेनेटरी नैपकिंस को महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को उपयोग के लिए दिया जाएगा, साथ ही उनसे फीड बैक लिया जाएगा।

टू कालर से प्रसारित हो रहे अश्लील विज्ञापनों पर लगाई जाये रोक

माही की गूंज, खंडवा। इन दिनों जैसे-जैसे डिजिटल कार्य बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हर साइडों पर साइड खोलते से ही विज्ञापनों की बौछार चालू हो जाती है जो कि उपभोक्ताओं के लिए शर्मिंदगी एवं दुख का कारण बनता जा रहा है। अब टू कालर से अश्लील विज्ञापन प्रसारित होने लगे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ ही केंद्र शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर शिवसेना प्रमुख गणेश भावसार ने रोष जताते हुए कहा कि, परिवारजनों द्वारा कॉल करने पर टु-कॉलर द्वारा अश्लील विज्ञापन परोसे जाना शर्मिंदगी महसूस करने के समान है। अनेकों बार इसे विज्ञापन व्यक्ति के मन मस्तिष्क को झंझोकर अपराध करने की प्रवृत्ति को जन्म देते है। इसी तरह अब तो टू कालर न भी अपने उपभोक्ताओं को अश्लील विज्ञापनों से आकर्षित करना चालू कर दिया है जो कि बहुत घिनौना कार्य है। श्री भावसार ने कहा कि जब सरकार पोर्न साइटों पर रोक लगा सकती है तो आखिर इस तरह के अश्लील विज्ञापनों पर क्यों नहीं? प्रशासन शासन द्वारा इस ध्यान दिया जाकर शीघ्र ही ऐसे अश्लील विज्ञापन प्रदाताओं पर कड़ी कार्रवाई कर लगाई जाना जनहित में होगा।

पथ विक्रेता योजना के तहत जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर

माही की गूंज, झाबुआ। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना के तहत जिले में इस वित्तीय वर्ष में 2 हजार 759 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध बैंकों में 1 हजार 939 हितग्राहियों के ऋण प्रकरण तैयार कर बैंकों में प्रस्तुत किए गए है। बैंकों द्वारा 1 हजार 539 प्रकरण स्वीकृत कर 1 हजार 413 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। इस योजना के तहत झाबुआ में 826, पेटलावद में 111, थांदला में 133, राणापुर में 128 तथा मेघनगर में 215 हितग्राहियों को ऋण वितरण किया गया है। इस योजना के तहत जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। कलेक्टर रोहित सिंह के विशेष प्रयासों से यह सम्भव हो सका है। इस योजना के तहत जारी वित्तीय वर्ष में 2 हजार 759 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध अब तक 3 हजार 322 हितग्राहियों का इस योजना के तहत पंजीयन किया गया है और इतने ही हितग्राहियों का सत्यापन किया जा चुका है।

अधिकारियों को कार्य संतोषजनक नही होने से एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश

- सरपंच, सचिव की शिकायतों की तत्काल जांच कर नोटिस दिए जाने के निर्देश - झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफकार्यवाही की जाए

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में झोला छाप डॉक्टरों की जांच के लिए विशेष मुहीम चलाई जाए और ऐसे डॉक्टर पाए जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। यह निर्देश कलेक्टर रोहित सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को दिए हैं। सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में जांच अभियान के दौरान पाए जाने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

कलेक्टर सिंह ने इस बैठक में समयावधि के लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन पत्रों के निराकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दें और लम्बित पत्रों का तत्काल निराकरण करें। इस बैठक में जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई और खाद्यान्न वितरण का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए आगामी एक सप्ताह में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही रामा, राणापुर तथा थांदला के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इन अधिकारियों को आगामी 5 दिवस में खाद्यान्न वितरण के कार्य में सुधार लाने का मौका दिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की सघन समीक्षा की गई और ऋण प्रकरणों को तत्काल स्वीकृत कर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई तथा राशि का तत्काल भुगतान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव की शिकायतों की तत्काल जांच कर नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही एक माह से शिकायत लंबित पाए जाने पर संबंधित का वेतन काटने और विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित की गई समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक

जीर्ण-शीर्ण भवनों को तत्काल खाली करने को निर्देश

कलेक्टर सिंह ने थांदला में बस स्टैण्ड के लिए स्थल का चिन्हांकन करने के कार्य की समीक्षा की और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को स्थल का चिन्हांकन शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होने लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसम्पत्तियों की जानकारी दर्ज करने के कार्य की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन शासकीय परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण है ऐसी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही अविवादित तथा अतिक्रमण से मुक्त परिसम्पत्ति ही पोर्टल पर दर्ज कराएं। उन्होने कहा कि नए भवन होने के बावजूद भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने वाले शासकीय भवनों का उपयोग किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे जीर्ण-शीर्ण भवनों को तत्काल खाली करें।

राजस्व वसूली को लेकर की नाराजगी जाहिर

इस बैठक में विभिन्न मदों में राजस्व वसूली कार्य की तहसीलवार समीक्षा की गई और राजस्व की वसूली में प्रगति कम पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। वसूली के लिए शिविर आयोजित कर राजस्व वसूली कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के तहत दर्ज 15 प्रकरणों में आरोपित राशि की वसूली कार्य की समीक्षा की कई और आरोपित राशि की वसूली की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य पदार्थो में मिलावटी मुक्त अभियान के तहत की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की गई और जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर जेएस बघेल, सहायक कलेक्टर आकाश सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद शिशिर गेमावत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एमएल मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला अनिल भाना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर एलएन गर्ग, डिप्टी कलेक्टर ज्योति परते सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, तहसीलदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मौजूद थे।

7 माह में मिली अनुकंपा नियुक्ति

माही की गूंज, खरगोन।

झाबुआ तहसील में भृत्य के पद पर कार्य करने वाले स्व. शकूर खान की अचानक किडनी फेल होने से 24 मई 2020 को देहांत हो गया था। परिवार में एकलौते कमाई करने वाले श्री खान के अचानक चले जाने से परिवार पर आर्थिक बोझ आ पड़ा। हालांकि उनके पुत्र करीम खान ने अपनी शिक्षा के बुते कई तरह की डिग्रियां कर ली थी, लेकिन पिता की मृत्यू तक वे एक अच्छी सेवा तलाश कर रहे थे। करीम खान ने हायर सेकेंडरी के बाद बीए, एमए, एमएसडब्ल्यू और फिर जरूरत होने पर पीजीडीसीए एवं सीपीसीटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रखी थी। लिहाजा जिला पंचायत में उन्हें आउट सोर्सिंग का कार्य मिला। इधर परिवार की तंगी के कारण हालात ठीक नहीं थे। दिवंगत शासकीय सेवक शकूर के पुत्र करीम खान ने सहायक ग्रेड-तीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन जिला झाबुआ में सहायक ग्रेड-तीन का सामान्य वर्ग में रिक्त पद नहीं होने से राजस्व विभाग के आयुक्त को नियुक्ति के लिए लिखा गया।

तहसील कार्यालय झिरन्या में मिली अनुकंपा नियुक्ति

राजस्व विभाग के आयुक्त ने आवेदक को जिला खरगोन में सहायक ग्रेड-तीन के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्त देने के लिए प्रकरण भेजा गया। प्रकरण को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने गंभीरता से लेते हुए शासकीय सेवक के परिवार में आश्रित सदस्यों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से कार्य को प्राथमिकता दी। बहरहाल शासकीय सेवक शकूर खान हाल मुकाम कैलाश मार्ग हुसैनी चौक झाबुआ के पुत्र करीम खान को तहसील कार्यालय झिरन्या में सहायक ग्रेड-तीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति पत्र अपर कलेक्टर एमएल कनेल ने गत मंगलवार को आयोजित हुए जनसुनवाई में प्रदान किया।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टायर प्लांट को बंद करने के जारी किए आदेश

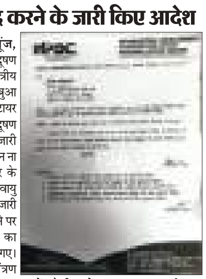

माही की गूंज, झाबुआ। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय धार द्वारा झाबुआ जिले में स्थापित सभी टायर प्लांट को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सम्मती की शर्तों का पालन ना करने एवं भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन ना करने पर उद्योग को बंद करने का आदेश जारी किए गए। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के पालन में एकेवीएन मेघनगर तथा वाम उर्जा टायर प्लांट का जल प्रदाय संयोजन व मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय कनेक्शन काट दिया गया है। इस हालत में अब यह उद्योग चलने की स्थिति में नहीं रहा। जानकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीवास्तव ने दी।

गौरतलब है इस उद्योग द्वारा मेघनगर क्षेत्र में अत्यंत प्रदूषण चलाया जा रहा था और कुछ समय पूर्व इस प्लांट में आगजनी की घटना भी हुई थी, जिसमें किस्मत से कोई जनहानि नहीं हुई, झाबुआ, मेघनगर और थांदला के फायर बिग्रेड ने आकर उक्त आग को बुझाया था।

कलेक्टर ने किया नाबार्ड द्वारा तैयार 4 हजार 50 करोड़ रुपए की संभाव्यता युक्त ऋण योजना का विमोचन

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जिले हेतु तैयार 4 हजार 50 करोड़ रुपए की संभाव्यता युक्त ऋण योजना का विमोचन किया।

इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक रामटेके ने बताया कि, इस ऋण योजना में भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे ऋण वितरण की दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि ऋण, कृषि अधोसरंचना, कृषि सहायक गतिविधियों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों, शिक्षा, आवास नवीनीकरन, ऊर्जा आदि हेतु 4049.65 करोड़ रुपए की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना बनाई गई है।

इस अवसर पर कलेक्टरेट सभागृह में आयोजित डीएलसीसी की बैठक में जिला पंचायत सीईओ ऋतुराजसिंह, एलडीएम भागीरथ प्रजापति एवं जिले मे कार्यरत सभी बैंको के प्रबन्धक सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।

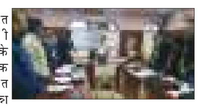

स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी बिदाई

माही की गूंज, पेटलावद। शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ बच्चू सिंह खोड़े की सेवानिवृत्ति पर बीएमओ एमएल चोपड़ा एवं अस्पताल स्टाफके द्वारा श्री खोड़े का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीएमओ श्री चोपड़ा द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी बच्चू सिंह खोड़े को साल श्रीफल एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया और बच्चू सिंह खोड़े के स्वस्थ रहने की कामना की। विदाई समारोह के उपरांत स्टाफके समस्त चिकित्सक गण भी मौजूद थे जिन्होंने विदाई समारोह में श्री खोड़े के कार्य की सराहना की इसी दौरान बीएमओ एमएल चोपड़ा ने अपने निजी वाहन में सेवानिवृत्त कर्मचारी को अस्पताल से बैठाकर घर तक पहुंचाया। गौरतलब है कि, पेटलावद स्वास्थ्य केंद्र में यह पहला मामला है कि, किसी कर्मचारी को इतना मान सम्मान के साथ विदाई समारोह करके अपने निजी वाहन से घर तक छोड़ा गया। इसी विदाई समारोह की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर चोयल, डॉक्टर बघेल, डॉ रावत, डॉक्टर डाबी, अखिलेश शोरोड़ा सहित स्टाफमौजूद रहा।

माही की गूंज, कुन्दनपुर। किसान आंदोलन के समर्थन मे कांग्रेसी युवाओं ने ग्राम कुन्दनपुर में रात्रि में मशाल जुलुस निकालकर केन्द्र सरकार का विरोध कर मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया।

माही की गूंज थांदला। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल के विरोध में देर शाम को थांदला में कांग्रेस ने मशाल जुलुस निकाला।

खरगोन को मिला एक्सलेंस इन डिजीटल गवर्नेंस डिस्ट्रीक का प्लेटीनम अवार्ड

माही की गूंज, खरगोन।

देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को खरगोन कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी और जिला विज्ञान व सूचना अधिकारी राजेंद्र पाटीदार को जिले का 'एक्सलेंस इन डिजीटल गवर्नेंस डिस्ट्रीक' का प्लेटीनम अवार्ड प्रदान किया। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की समस्त राजधानियों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत भोपाल के विंध्याचल भवन में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह और विज्ञान अधिकारी श्री पाटीदार ने यह अवार्ड डिजीटल रूप में प्राप्त किया। खरगोन जिले को यह अवार्ड जिला प्रशासन की वेबसाईट को डिजीटल इंडिया को प्रोत्साहन देने की दिशा में देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ वेबसाईट के तौर पर चुना गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि, यह डिजीटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार के विजन को दर्शाता है, जो नागरिकों को समर्थ और उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करते हुए देश को सुपर पॉवर बनाता है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने संबोधन में कहा कि, वर्ष 2020 कोविड-19 महामारी के तौर पर रहा है, जो अपनी अंतिम दौर में है।

क्यों खास है जिला प्रशासन की वेबसाईट ?

जिला प्रशासन की वेबसाईट को देश की सबसे उत्कृष्ट वेबसाईट में चुना गया है। इस वेबसाईट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, इसमें शासन की लगभग 90 योजनाओं की पूरी-पूरी जानकारी उपलब्ध है। साथ ही योजना के विवरण के अलावा उसके आवेदन, विभाग, पात्रता के बिंदू, आवेदन किसे प्रदान करना, आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज और विभाग को सौंपने की तमाम जानकारी उपलब्ध है। साथ ही वेबसाईट पर जिले के छोटे-बड़े कई पर्यटन स्थलों की जानकारी व फोटो के अलावा जिला प्रशासन के आदेश और प्रतिदिन आयोजित होने वाली बैठकों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। वहीं यह वेबसाईट पूरी तरह अपडेटेड है।

रोजगार मेले में 190 युवक युवतियों का नौकरी के लिए चयन

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर रोहित सिंह के प्रयासों से जिले में जनपद स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रंखला में झाबुआ में ग्रामीण आजीविका मिशन भवन में तथा राणापुर में जनपद पंचायत सभा कक्ष में जनपद स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में 5 कम्पतिनयों ने हिस्सा लिया। झाबुआ में 435 युवक-युवतियों का पंजीयन किया गया। इनमें से 138 युवक-युवतियों का कम्पनियों द्वारा नौकरी देने के लिए चयन किया गया है। इसी प्रकार राणापुर मेले में 122 युवक-युवतियों का पंजीयन किया गया। जिसमें से कम्पनीयों द्वारा 52 युवक-युवतियों का चयन किया गया है। मेले को सफल बनाने में महाप्रबंधक जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र वीरेन्द्र सिंह ईश्क्या, रोजगार अधिकारी टीएस डुडवे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चन्दरसिंह मण्डलोई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का विशेष योगदान रहा।

चिटफण्ड कंपनी के ऐजेंट की जमानत याचिका निरस्त

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा ने अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा गया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि, वर्ष 2011 से 2015 तक आरोपी गौरव गोस्वामी चिटफण्ड कंपनी आर के आर एग्रो को-आपरेटिव सोसायटी का ऐजेंट था। आरोपी ने कई आसपास के गांवों में आर के आर एग्रो सोसायटी के नाम से कई लोगों के खाते खुलवाए थे, खाते खोलते समय आरोपी गौरव द्वारा यह बताया गया था कि, कंपनी 6 वर्ष के पश्चात् अधिक ब्याज सहित रूपए वापस लौटा देगी। इस प्रकार आरोपी द्वारा कई खाताधारकों को अधिक से अधिक ब्याज सहित रूपए दिलवाने व लालच देकर कई खाता धारकों से रूपए कलेक्शन करता था एवं आरोपी द्वारा समस्त खाता धारकों व ग्राहको से बीमा करने के नाम पर राशि ली जाती थी और पालिसी की जाती थी। लेकिन कंपनी द्वारा नियत समय से पूर्व ही खाता धारकों से षड्यंत्र पूर्वक धोखाधडी से उनसे ली गई राशि का गबन कर आरोपी गौरव गोस्वामी भाग गया।

इस पर पुलिस थाना वरला में कई खाता धारकों द्वारा आरोपी व चिटफण्ड के संचालक व कई ऐजेंटों के खिलाफरिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा आरोपी गौरव व संचालक एवं कई ऐंजेटों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

आवारा गोवंश का सहारा बने कचरूलाल, रोज करते है देखभाल

गौचर भूमि पर गौशाला बनाने की मांग पर जवाबदार नहीं ले रहे कोई सुद

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के पिपलोदा तहसील के गांव बचोडीया के निवासी कचरूलाल पिता बगदीराम भील विगत 20 वर्षो से अपने निजी सिंचित जमीन पर 12 सौ स्क्वायर फीट का एक बरामदा बनाकर उसके आस-पास बरसाती का तम्बू बनाकर बाजार में जो अवारा गोवंश घूमते है जिन्हें लाकर उनका भरण-पोषण कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में उनकी धर्म पत्नी रामकन्या बाई वृद्ध होने के बाद भी कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान कर रहीं हैं। कचरूलाल का कहना है कि, पूर्व में हमारे समाज के लोग थोडे से लालच में आकर पशुओं का वध करने वाले व्यापारियों के चक्कर में आकर पशुओं को कोसों दूर पैदल लाने ले जाने का काम किया करते थे, अगर रास्ते में पकडे जाते तो व्यापारी तो बच जाते पर हमारे समाज के लोगों को सजा भुगतान पडती थी। समाज के इस काम का पश्चाताप करते हुए मैरे मन मे विचार आया कि, क्यों नहीं आवारा पशुओं को कत्ल खाने जानें के बजाय इन पशुओं को अपने प्रयासों से पालन पोषण किया जाए ओर मैंने यही सोचकर 20 वर्ष पूर्व यह प्रतिज्ञा ली थी कि, मैं ग्राम पंचायत बचोडीया के

अन्तर्गत करीब 150 बीघा गोंचर भूमि हैं जींस पर लोगों द्धारा अतिक्रमण किया जा रहा है उसके बजाय उक्त गोंचर भूमि पर गौशाला का निर्माण किया जाए, जिसके कारण अतिक्रमण से गोंचर भूमि वंचित हो जाएगी, वही आवारा गोवंश का पालन-पोषण हो सकेगा। कचरूलाल ने बताया कि, मैंने कई बार ग्राम पंचायत के साथ जन प्रतिनिधियों से गौशाला बनाने हेतु उक्त गौचर भूमि के लिए निवेदन किया, किन्तु किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, अब मुझे विश्वास है कि आपके इस समाचार के माध्यम से शासन व प्रशासन तक मैरी आवाज पहुंचेगी ओर गौशाला के लिए पहल होकर निर्णायक स्थिती में पहुंचेगे वहीं गौशाला बनने पर ही मैरी डाढी-कटिंग बनाने की मनंत ले रखी जो भी पूर्ण होंगी।

ज्ञात रहे कचरूलाल अपनी धर्म पत्नी के साथ बचोडीया गांव छोडकर एक किलोमीटर दूर खेत पर ही रहकर करीब 24 अवारा गोवंश को लाकर उनका भरण-पोषण कर रहे हैं, कचरूलाल का कहना है कि, मेरे निजी तीन बीघा जमीन में इन गोवंश के लिए मक्का, चरी बो रखी है वही आस-पास के गांव में जाकर किसानों से निःशुल्क सुकला इकट्ठा कर इनका भरण-पोषण किया जा रहा है, ये ही नहीं इनके पिने के पानी के लिए छोटी खेर बना रखी है, मैरी पत्नी भी मवेशीयों को बाल्टी से भी पानी पिलाती है व गोबर समेटने का काम भी करतीं हैं। गोवंश का दूध नहीं निकाला जाता है बच्चे को ही दूध पिलाया जाता है। कचरूलाल ने बताया, वर्ष 2015 में निजि भूमि पर प्याज भण्डारण हेतु उप सहायक संचालक उघान रतलाम को आवेदन पत्र दिया गया था व उनके आदेशों अनुसार तीन लाख रुपए की लागत से 50 मेट्रिक टन प्याज का भण्डारण कर सकें इस हेतु एक गोदाम बनाया गया था, किन्तु उक्त भवन निर्माण की राशी अभी तक प्राप्त हुईं हैं। जानकारी लेने पर यह पाया गया कि, आपका गोदाम निजि भूमि पर न होकर गोंचर भूमि पर बनाया गया है। अगर बचोडीया गांव में गोंचर भूमि पर गौशाला का निर्माण किया जाता है तो इस गोदाम के साथ निःशुल्क सेवा देने को तेयार है।

कलेक्टर तथा अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी निराकरण के निर्देश विभागों को दिए

माही की गूंज, रतलाम।

जिला मुख्यालय पर 29 दिसंबर मंगलवार से जनसुनवाई पुनः प्रारंभ की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन ने आवेदकों के आवेदन की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए, इस दौरान 42 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में ग्राम सेलजदेवदा तहसील रावटी के बालू देवदा ने उसके पड़ोसी द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा कर सड़क बनाने के संबंध में विवाद करने पर आवेदन दिया जिसके निराकरण के लिए तहसीलदार रावटी को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार मोहन परदेसी ने आवेदन दिया कि, वे ग्रामीण अंचल के निजी विद्यालय में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, उनकी पुत्रियां महाराष्ट्र, पुणे में अध्ययनरत हैं उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है, कलेक्टर ने आवेदन पर सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। महेश मैडा इंदिरा नगर रतलाम ने सूदखोरों से निजात दिलवाने हेतु आवेदन दिया जिस पर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए। ग्राम सालाखेड़ी के मनोहरलाल ने बिजली के बिल की राशि ज्यादा आने की शिकायत की, शिकायत निवारण के लिए अधीक्षण यंत्री विद्युत को निर्देशित किया गया। भारोड़ा तहसील नामली के विश्राम पिता नाथू एवं रामकन्याबाई ने आवेदन दिया कि, 8 लेन निर्माण के लिए आसपास की शासकीय भूमि की खुदाई कर मिट्टी तथा मोर्रम ले जाई जा रही है, बिना किसी नोटिस, बिना किसी मुआवजा राशि दिए ही हमारी खड़ी फसलों को नुकसान करते हुए 8 लेन निर्माण कंपनी द्वारा खुदाई की जा रही है। आवेदन पर तहसीलदार नामली को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।

फिट इंडिया कैंपियन के तहत सायकल रैली का आयोजन हुआ

माही की गूंज, अलीराजपुर।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में फिट इंडिया कैंपियन ''फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज'' के तहत सायकल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर सुरेशचंद्र वर्मा और जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सुश्री सन्तरा निनामा उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियो को खेलों के प्रति प्रेरित कर कहा कि, प्रतिदिन अभ्यास करें जिससे की मानसिक व शारीरिक विकास हो सके।

अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने खिलाड़ियों को खेलों के प्रति सजग रहने व नियमित अभ्यास करने की बात कही। रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत करने से पहले कन्या पूजन किया गया जिसमें कन्या को तिलक, श्रीफल, माला पहनाकर व उपहार के तौर पर स्पोर्ट्स टी शर्ट प्रदान की गई। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सुभाष महोबिया, पूर्व व्यायाम प्रशिक्षक खेमचंद्र सिकरवार, डीसी मिश्रा, भूपेन्द्र बघेल, पिकेश वर्मा, अजय रिछारिया (बॉक्सिंग कोच), संजय पवार, हेमन्त मुजाल्दे, खेल युवा संमन्वयक दिलीपसिंह बघेल, कारसिंह सस्तिया, सुश्री ज्योति राजपूत, आनंद निमौरे सहित अन्य उपस्थित थे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमित्त समर्पण अभियान के तहत गांव-गांव निकल रही वाहन रैली

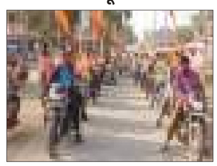

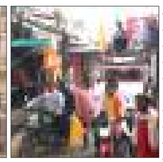

माही की गूंज, झकनावदा/खवासा/ सारंगी।

राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण रैली गांव-गांव में वाहन रेली निकाली जा रही है।

झकनावदा प्रतिनिधी अनुंसार स्थानीय वेराई माता चौक, इंदिरा कॉलोनी झकनावदा से वाहन रैली श्रीराम की पूजा अर्चना करके जय-जय सियाराम के जय घोष एवं रामलला का ध्यान करो, मंदिर का निर्माण करो, गायन के साथ निकाली गई। रैली सर्वप्रथम मेन बस स्टैंड से निकलकर हरिजन मोहल्ला, मिस्त्री मोहल्ला, गारी मोहल्ला होते हुए सदर बाजार से सीरवी मोहल्ला, इंदिरा कॉलोनी होते हुए फिर वेराई माता चौक पर प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ कर एवं प्रसादी वितरण कर रैली का समापन हुआ।

सारंगी प्रतिनिधी अनुंसार शनिवार को हिंदू समाज के सैकड़ों युवाओं में बजरंग दल के सदस्यों ने वाहन रैली निकाली, रैली स्थानीय मंडी परिसर से शुरु होकर बस स्टैंड, सदर बाजार, पाटीदार मोहल्ला, भैरवनाथ बस स्टैंड, रतलाम रोड, इमली चौक होते हुए बाछीखेड़ा, करवड, मांडन, मठमठ होते हुए रैली कसारबड़ी पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ।

खवासा प्रतिनिधी अनुसार बामनिया मार्ग स्थित मंडी परीसर से हिन्द महासभा की सामुहीक वाहन रैली निकली। उक्त रैली बस स्टेंड, जैन मंदिर, निम चौक, पाटीदार मौहल्ला होते हुए गणेश मंदिर तिराहे से नरसिंगपाडा, भामल होते हुए वापसी वाहन रैली खवासा मंडी परीसर पंहुची जहां पर रैली का समापन हुआ।

पाले से बचाव के लिए कृषकों को सलाह

माही की गूंज, शाजापुर। शाजापुर किसान कल्याण तथा कृषि विकास परियोजना संचालक आरपीएस नायक ने बताया कि, वर्तमान में अधिक ठंड पड़ने के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अगर इसी तरह तापमान में गिरावट जारी रही तो पाला पड़ने की संभावना है, जिससे की रबी फसलों खास कर चना, मसूर, सरसों में भारी नुकसान होता है। परियोजना संचालक नायक ने जिले के कृषक भाईयों को सलाह दी है कि, पाले से बचाव के लिए फसल में हल्की सिचाई करें। पाले से बचाव के लिए सल्फर डस्ट 8 से 10 किलों प्रति एकड़ छिडकाव करे या वेटेबल सल्फर 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में स्प्रे करे, थायों युरिया 7 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पम्प से स्प्रे करे, व्यपारिक गंधक का तेजाब सल्फ्युरिक एसिड 15 एमएल प्रति 15 लीटर पानी में स्प्रे करे, ग्लूकोज सादा 25 से 30 ग्राम प्रति पम्प स्पें करे।

कलेक्टर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम की जनसुनवाई

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर दिनेश जैन ने जिले की 12 ग्राम पंचायतों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क किया। इन ग्राम पंचायतों के सरपंचो ने ग्राम की जरूरतों की जानकारी दी और ग्राम पंचायतों में उपस्थित आमजनों ने भी अपनी समस्याएं बताई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही जनसुनवाई मे जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मिशा सिंह, कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण .रविन्द्र वर्मा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वीएस चौहान, सीएमएचओ डॉ. आर निदारिया, विद्युत वितरण कंपनी डीई डीके श्रीवास्तव, एएसएलआर अकलेश मालवीय भी उपस्थित थे।

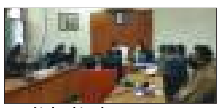

वीडियो कांफ्रेंसिंग में जनपद पंचायत शाजापुर की ग्राम पंचायत झोंकर, रेहली एवं हनोती। मो. बड़ोदिया की ग्राम पंचायत किठोर, मखावद एवं खेड़ावद। कालापीपल की ग्राम पंचायत पिपल्यानगर, भूरिया खजूरिया एवं लसुड़ियाघाघ तथा शुजालपुर की ग्राम पंचायत अवंतिपुरा, भोगीपुर एवं उगली शामिल हुई।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि, ग्राम पंचायतों से मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने सरपंचो से कहा कि, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए ग्रामीणों को सतत् प्रेरित करते रहें। कलेक्टर ने ग्रामों की पेयजल समस्या, आंगनवाड़ियों द्वारा सूखा खाद्यान्न वितरित करने, उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त होने, आयुष्मान कार्ड बनाने, फसल बीमा, पशुओं के बीमा आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की। खाद्यान्न पर्ची के नहीं मिलने की शिकायत का निराकरण करने के लिए कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारी को तथा अतिक्रमण की समस्या का हल करने के लिए संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया।

रामोत्सव निधि संग्रह का खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र के छोटी सरवा से हुई शुरूआत, 100 गांवों की प्रत्येक परिवार से निधि संग्रह का आह्वान

माही की गूंज, कुशलगढ (राज.)। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के बनने वाले भव्य रामलला मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और से आयोजित रामोत्सव निधि संग्रह अभियान की बैठक कुशलगढ़ उपखंड के घाटा क्षेत्र के छोटी सरवा स्थित सरस्वती विद्या निकेतन परिसर में निधि संग्रह के जिला प्रमुख गोपाल राव, आरएसएस के जिला कार्यवाह मनोज शर्मा, विहिप के जिला मठ मंदिर प्रमुख विकास भट्ट, संगठन मंत्री बापुसिंह राठौड़ के आतिथ्य में आयोजित हुई, जिसमें खंड छोटी सरवा के प्रत्येक 100 गांवों से प्रत्येक हिन्दू परिवार से निधि संग्रह का आह्वान किया तथा निधि संग्रह कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र जोशी, राकेश वडखिया, तोलसिंह हटिला, मानसिंह डाबी, सादर भाई, गोपाल सिंह गेहलोत, पोपटलाल पटेल, भूपतसिंह राठौड़, बहादुर सिंह राठौड़, राजेश टेलर, महेश टेलर, बल बहादुर सिंह गौड़ सहित रामभक्त मौजूद रहे। उक्त जानकारी खंड प्रमुख जालुसिंह गामड ने दी।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 406 हितग्राहीयो को माना पात्र तो 32 अपात्र

माही की गूंज, मेघनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राही जिन्हें केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा ढाई लाख का अनुदान मकान बनाने के लिए दिया जाता है, नगर परिषद मेघनगर के 438 हितग्राहियों की डीपीआर का अनुमोदन कलेक्टर कार्यालय में विगत 1 वर्षों से लंबित था। हितग्राही आवास योजना में लाभ हेतु काफी परेशान हो रहे थे, ऐसी परिस्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी विकास डावर व वर्तमान प्रशासक व अनुविभागिय अधिकारी एलएन गर्ग द्वारा कलेक्टर रोहित सिंह से हितग्राहियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। कलेक्टर रोहित सिंह ने नगर परिषद मेघनगर के 438 हितग्राहियों में 32 हितग्राहियों को विभिन्न कारणो से अपात्र कर शेष 406 आवास हितग्राहियों को पात्र मान उन्हें अनुमोदित कर राशि स्वीकृत की, जिसके बाद हितग्राहियों की समस्या का समाधान हुआ। शासन से राशि प्राप्त होते ही शीघ्र ही संबंधित हितग्राहियों के खातों में राशि प्रदाय की जाएगी।

भाजपा मंडल द्वारा मामाजी की 22वी पुण्यतिथि मनाई गई

माही की गूंज, थांदला।

आदिवासी समुदाय के प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य, पत्रकार, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक उत्थान में मामा बालेश्वर दयाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। मध्यप्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात राज्य के श्रद्धालु हर वर्ष मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि मनाने आते है। मामा बालेश्वर दयाल ने गोबर नाम से अखबार निकाला था, जिसके माध्यम से मामाजी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम स्वाधीनता आंदोलन 40 के दशक में मामा बालेश्वर दयाल व कन्हैयालाल वैध ने भाग लिया था, स्व. मामा बालेश्वर दयाल की 22 वी पुण्यतिथि पर वरिष्ठ नेता अशोक अरोरा व मंडल अध्यक्ष समर्थ उपाध्याय ने माल्यार्पण कर मामाजी को याद किया कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष नटवर पवार, पूर्व मंडल महामंत्री किशोर आचार्य, मंडल उपाध्यक्ष सुरेश राठौर, राकेश सोनी, समाज सेवी पूनम मिस्त्री, अजय सेठिया, उपाध्यक्ष पारू पारगी मंडल मंत्री कन्ना वसुनिया, राजू गरवाल, सुजीत भाभर, पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष गोपाल वैरागी, पिटर बबेरिया, गजेंद्र चौहान, कपिल पाठक, कांतिलाल परमार, राजू धानक, कार्यकारणी सदस्य मथियास निनामा, मांगू निनामा, संजय परमार, करन भूरिया आदि उपस्थित थे, कार्यक्रम का आभार मंडल महामंत्री सुनील पणदा ने माना।

अवैध तरीके से नामान्तरण करवा कर लिया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, निर्माण से मार्ग हो रहा बाधित

जनसुनवाई के पहले दिन नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर लगे आरोप

माही की गूंज, पेटलावद।

मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के शुरू होते ही लोग अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे, जनसुनवाई के पहले ही दिन नगर परिषद में नामान्तरण में की जा रही हेरा-फेरी का बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता रमेश धानूक निवासी राजपुरा पेटलावद ने आवेदन देते बताया कि, वार्ड क्र. 14 गौरघाटी राजापुरा पेटलावद में स्थित उकार पिता नारायण धानुक हरिजन के दोनों मकानों को तोड़कर स्थगन आदेश जारी करने की मांग रखी, अवैध नामान्तरण गौरघाटी राजापुरा मोहल्ला वार्ड क्र. 14 पेटलावद निवासी स्व. उंकार पिता नारायण धानुक हरिजन के नाम नगर पंचायत पेटलावद में सम्पत्ति भवन कर रिकार्ड में दो मकान दर्ज होने के बाद भी नगर पंचायत ने गुलाबबाई पति रतनलाल दगल, अनसुईया पति गणेश मार, ज्योति पति गोविन्द मार और सविता पति जितु दगल सभी निवासी गौरघाटी राजापुरा वार्ड क्र. 14 पेटलावद में नगर पंचायत कर्मचारियों की मिली भगत से गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर अवैधानिक तरीके से उंकार पिता नारायण धानुक हरिजन के एक मकान पर गुलाबबाई पति रतनलाल दगल ने नगर पंचायत में नाम दर्ज करवा लिया है।

शिकायतकर्ता ने अवैध तरीके से हुए नगर पंचायत में नामान्तरण को निरस्त कर स्व. उंकार पिता नारायण धानुक हरिजन का पूर्व की भांति पूर्ण नाम चढ़ाने की मांग रखी। गुलाबबाई तथा नगर पंचायत की मिलीभगत से अवैध नामान्तरण की आड़ में दोनों मकानों की आड़ में नगर पंचायत द्वारा दिए गए वर्ष 2019 में आवासीय पट्टे गुलाबबाई तथा गुलाबबाई के पूरे परिवार ने अवैध तरीके से प्राप्त किए है। सभी लोगों ने गलत तरीके से प्राप्त किए पट्टों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर पंचायत में इनके द्वारा प्रस्ततु दस्तावेजों की जांचकर पट्टे निरस्त करते हुए आवास योजना में स्वीकतृ राशि पर तथा किए जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि से जो भवन निर्माण किया जा रहा है वह भूमि स्व. उंकार नारायण धानुक हरिजन की है तथा उक्त भूमि के अलावा पास में आम लोगों के आने-जाने के रास्ते करीब 6-7 फीट भूमि पर अवैध अतिकमण कर भवन निर्माण किया जा रहा है, जिससे आम लोगों का रास्ता रोक दिया गया है। उक्त लोगो द्वारा किए जा रहे उंकार पिता नारायण हरिजन एवं सरकारी भूमि के रास्ते पर अवैध निर्माण कर किए जा रहे निर्माण को तत्काल रूकवाने के आदेश होकर जांच के भी आदेश भी दिए जाने के संबंध में शिकायत जनसुनवाई में दर्ज करवाई।

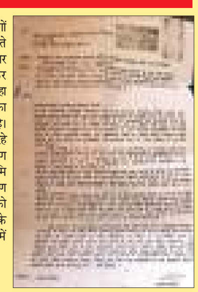

मात्र 11 आवेदन आए, कई शिकायते बिना निराकरण के ही पड़ी

कोरोना काल में बन्द हुई जनसुनवाई में मंगलवार को अधिकारियों के समक्ष मात्र 11 आवेदन ही प्राप्त हुए जिसके पीछे प्रचार-प्रसार का अभाव होना बताया जा रहा है। वहीं जनसुनवाई से पूर्व एसडीएम कार्यालय में की गई शिकायतो का निराकरण आज तक नही हो सका है अब जन सुनवाई कार्यक्रम में आने वाले आवेदनों पर कब और कैसी कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा।

चार बदमाश हुए जिला बदर

माही की गूंज, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा 4 बदमाशो को जिला बदर किया गया, थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ईसरथुनी निवासी राकेश पिता जगदीश धाकड तथा थाना माणकचौक अन्तर्गत सिलावटों का वास निवासी महेन्द्र पिता यशवंतसिंह राजपूत को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6-6 माह के लिए तथा शैरानीपुरा निवासी गफ्फार खान पिता ईशाक खान एवं पुलिस थाना सैलाना अन्तर्गत बागरीखेडी सैलाना निवासी राजू उर्फ राजेश पिता बालू बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपीगण जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

मोबाईल लूटेरों को युवाओ ने धर-दबोचा

माही की गूंज, थांदला।

मूकेश बंजारा की चाय की होटल पर कार्य करने वाले ईतेश का मोबाईल लुटेरे लुटकर ले गए थे युवाओ की सक्रीयता से लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आए। 27.दिसम्बर की रात 3 व्यक्ति चाय पीने के लिए होटल पर आए, चाय पीने के बाद फरियादी ईतेश का मोबाइल छीनकर मारपीट कर मोटर सायकिल से भाग गए। फरियादी के चिल्लाने पर थांदला के रहवासी होटल संचालक मुकेश, युवराज, अश्विनी, राकेश के साथ ईतेश द्वारा मोटर सायकिल से आरोपियों का पिछा कर आरोपियों को पकड़ा और चोरी हुए मोबाईल के साथ आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द किया। फरियादी की रिपोर्ट पर अजीत पिता कमल बसोड (21), संतोष पिता सोहन बसोड (27), अटिल पिता संजय बसोड (19) निवासी अयोध्या बस्ती झाबुआ पर थाना थांदला में अपराध क्रं. 584/2020 धारा 392 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने मुकेश, युवराज, अश्विनी, राकेश, ईतेश का आभार व्यक्त किया।

मोनिका शर्मा को मिला सेलिब्रिटी मैकअप आर्टिस्ट का अवार्ड

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

भोपाल के मान्स भवन पर प्रदेश स्तरिय ब्युटी अवार्ड मे चंद्रशेखर आजाद नगर की मोनिका शर्मा को सेलिब्रिटी मैकअप आर्टिस्ट का अवार्ड फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के हाथों दिया गया। उक्त अवार्ड शो में प्रदेश स्तर के कई मैंकअप आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था, इन सभी आर्टिस्टो कों पराजित कर मोनिका शर्मा का सर्वश्रेष्ठ मैकअप रहा जिन्हें फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का मैकअप करने का मौका मिला। इस शो के ऑग्रेनाइजर ममता शर्मा एवं राकेश बाटलाजी थे। मोनिका शर्मा द्वारा अलीराजपुर जिले के कई ब्यूटीशन को आगे बढ़ने मे अग्रिणीय भूमिका अदा की।

मोनिका शर्मा ने बताया कि, जनवरी माह मे राजधानी भोपाल मे हमारे द्वारा ऑयकन इण्डिया शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे भारत की उच्च स्तरीय ब्यूटीशन भाग लेगी जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। अपनी इस कामयाबी पर मोनिका शर्मा ने अपने परिजनों एवं मित्रों को आभार व्यक्त किया।

आर्थिक अनियमितता के बाद नपा अध्यक्ष को मप्र शासन ने हटाया पद से

जांच में हुआ खुलासा, नहीं लड़ सकेगी अगला चुनाव

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग सचिव अजयसिंह गंगवार ने 23 दिसम्बर को एक आदेश जारी कर आलीराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सेना पटेल को पूर्व में परिषद द्वारा किए गए एक दुकान आवंटन के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें नपा अध्यक्ष पद से तत्काल पृथक कर तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश भी जारी कर दिए है। साथ ही यह भी आदेश दिए गए कि, वे अगली पदावधि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष पद धारण नही कर सकते है।

यह है पूरा मामला

शहर में बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी के लिए आरक्षित कक्ष को दुकान बनाकर नीलामी कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन नपा के पूर्व की नपा परिषद न्यायालय में इस निर्माण पर स्टे की कार्रवाई में हलफनामा दाखिल कर वादा कर चुकी थी कि, यहां पुलिस चौकी कक्ष का ही निर्माण हुआ हैं। उक्त हलफनामा न्यायालय में देने के बावजूद नपा परिषद ने इस कक्ष को 9 लाख में नीलाम कर दिया। जिसकी शिकायत तत्कालीन नपा उपाध्यक्ष विक्रम सेन ने की थी। सूत्रो अनुसार इसका बाजार मूल्य 50 लाख रुपए के लगभग हैं।

जांच में पाया कि, बस स्टैंड पर बुनियादी शाला के पास कक्ष नम्बर 2 की नीलामी के सम्बंध में परिषद की स्वीकृति के बिना ही विज्ञप्ति जारी की थी और उसे सुरेशचन्द्र कुमरावत को 9 लाख रुपए की बोली में आवंटित कर दिया था, लेकिन उसमें नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 की उपधारा 3 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार 50 हजार से अधिक मूल्य की दुकान नीलामी के सम्बंध में शासन से स्वीकृति प्राप्त की जानी थी, जो नही की गई। वहीं जो मूल्य निर्धारित किया गया था उससे 6 लाख रुपए कम में दुकान नीलाम कर दी गई, ऐसी और भी कई अनियमित्ताए उक्त निलामी में पाई गई। अतः इस शिकायत का निराकरण करते हुए शासन ने नपा अध्यक्ष को दोषी ठहराते हुए अयोग्य घोषित कर दिया।

सूत्रों अनुसार तत्कालीन नपा परिषद द्वारा इसी तरह की अनेक आर्थिक अनियमित्ताओ की शिकायत की जांच भी शासन के विभिन्न स्तर पर जारी बताई जा रही हैं।

सामने आया नपा अध्यक्ष सेना पटेल का पक्ष

इस पूरे मामले को लेकर नपा अध्यक्ष श्रीमती सेना पटेल ने एक मीडिया संस्थान के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि, इस मामले में पहले एक आदेश जारी होता है, जिसमे मुझे नही बल्कि सीएमओ को दोषी करार देते हुए उन पर 10 लाख रूपए का जुर्माना किया गया था। वहीं आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि, उन्हें यह सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होने दुकान का गलत तरीके से आवंटन किया और नगर पालिका अध्यक्ष को भी मामला संज्ञान में नही लाया गया। अब उसी मामले में एक ओर फैसला यह साबित करता है कि, कैसे राजनीतिक द्वेष, दुर्भावना के चलते यह कार्रवाई की गई है। इसमें मैं कहीं भी दोषी नही हूं, मैं अपने वकीलों से सलाह ले रही हूं, इस फैसले को हम उचित प्लेटफार्म पर चेलेंज करेंगे।

तत्कालीन नपा उपाध्यक्ष विक्रम सेन ने बताया कि, आमजन की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों, अधिकारियों को बसस्टैंड स्थित अन्य दुकानों के शेड व पेड़ो के नीचे कड़ी धूप, भारी वर्षा में प्रताड़ना से स्थायी रूप से बचाने हेतु पूर्व नपा परिषद से इस कक्ष को पुलिस चौकी हेतु सुरक्षित रखने की लड़ाई मैंने ही लड़ी थी और इस कक्ष को तत्कालीन नपा परिषद के निर्णायक गण ने जनहित को ताक पर रखकर इसे दुकान के रूप में नीलाम कर दिया है।

रेत माफियाओं के खिलाफ राजस्व व खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई

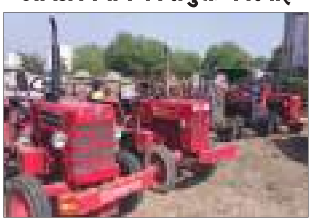

माही की गूंज, शाजापुर।

खनिज, राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रेत माफिआओं के खिलाफ बडी कार्रवाई की है। कलेक्टर दिनेश जैन के आदेशानुसार शाजापुर में रेत, खनिज एवं उत्खनन माफिआओं के खिलाफकार्रवाई करने के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया है, जिसके चलते संयुक्त विभागो के दल ने कालापीपल, मोहन बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना, अवन्तिपुर बड़ोदिया तहसीलो में रेत माफिआओ के खिलाफ अभियान छेड रखा है। रेत, मुरम व गिट्टीयो से भरे ट्रेक्टर-ट्रालीयो को रोककर उनकी रॉयल्टी चेक की, चालकों के पास जब रॉयल्टी नहीं मिली तो विभागो की टीम ने रेत, मुरम व गिट्टी का अवैध व्यवसाय करने पर 26 वाहनों को जब्त कर इलाके के संबंधित पुलिस थानो व तहसील कार्यालयों की सुपुर्दगी में रखवाकर अवैध परिवहन व भंडारणकर्ताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) अधीनियम 2019 के नियम 20 के उपनियम के अंतर्गत अवैध रेत, खनिज भंडारण का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला खनिज अधिकारी आरएस उइके ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर निरंतर राजस्व, पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

गूंज असर

महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए 19 मजदूर सकुशल घर लौट

स्थानीय प्रशासन की ओर से नहीं की गई कोई पहल, सर्च वारंट की प्रक्रिया भी दो तहसील के बीच उलझी रही, समाज सेवा संस्था पहुंची मजदूरों तक

माही की गूंज, पेटलावद।

अधिक मजदूरी का लालच देकर तीन गांवों के 55 मजदूरों को दो ठेकेदार अपने साथ महाराष्ट्र लक्जरी बस में ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें गन्ना काटने के काम पर लगाया, तीन ग्रुप बनाकर अलग-अलग जगह भेजे। 19 लोगों का एक ग्रुप महाराष्ट्र के बीड़ जिले में रखा, 15 को कर्नाटक भेजा और 23 मजदूरों को महाराष्ट्र में ही दूसरी जगह भेज दिया। उनसे सुबह 4 बजे से रात 1 बजे तक काम कराया जाता। अन्य राज्यो में गए मजदूर भाग आए और अपने गांव पहुंच गए उनके साथ हुई ज्यादती की जानकारी दी। जिसके बाद महाराष्ट्र में फंसे 19 मजदूरों से उनके परिजनों द्वारा लगातार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी प्रकार का संपर्क नही होने के कारण मजदूरों के परिजनों ने बामनिया चौकी पर मामले में आवेदन देकर मजदूरों को छुड़वाने की मांग की।

स्थानीय प्रशासन ने नही ली सूद, सर्च वारंट के लिए भी होना पड़ा परेशान

पुलिस के पास मामला जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, इसलिए परेशान मजदूरो के परिजनो ने पेटलावद एसडीएम में सर्च वारंट के लिए आवेदन पेश किया था, लेकिन पेटलावद तहसील के 5 मजदूरों के लिए सर्च वारंट मिल गए, क्योकि बाकी मजदूर थांदला तहसील के ग्राम चापनेर के होने से उनके लिए अनुभाग थांदला में आवेंदन देने को कहा गया।

थाना पेटलावद और विकास खण्ड थांदला होने से आई परेशानी

ग्राम चापनेर का थाना क्षेत्र पेटलावद लगता है, जबकि विकास खण्ड थांदला होने से परेशानी हो गई, दोनों अनुभाग में अधिकारीयो के बीच शंसय की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले में कोई ज्यादा रुचि नही दिखाई गई और जागरूक समाज सेवी संस्था के माध्यम से बंधक बनाए गए मजदूर घर आने में सफल रहे।

दिनेश गेहलोत का सराहनीय रहा सहयोग, दाहोद में बैठकर महाराष्ट्र मजदूरों तक पहुंची टीम

गूंज द्वारा मामला प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद दाहोद (गुजरात) के दिनेश गेहलोत ने गूंज से मामले की जानकारी लेकर अपनी टीम को एक्टिव कर, टीम की पूरी एक्टिविटी की जानकारी गूंज के पास और गूंज से मामले की जानकारी एसडीओपी पेटलावद को भेजी जाती रही। वाहन चालक मालक, सामाजिक कार्य क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल बैरागी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दिनेश गेहलोत, महाराष्ट्र मराठवाडा अध्यक्ष फिरोज शेख एवं महाराष्ट्र टीम जिसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दिनेश गेहलोत के द्वारा रतलाम बस संचालक समसुद्दिन लोहार से संपर्क कर आंबा जोगाई, मुशा ईब्रहिम के आधार कार्ड की खोज की उसके बाद महाराष्ट्र मराठवाडा अध्यक्ष फिरोज शेख को अपनी टीम के साथ आंबा जोगई, मुशा इब्रहिम के घर भेजा उसके बाद मजदूरों तक मराठवाडा टीम पहुंची और मजदूरों को वहा से छुड़ाया गया, जिसमें वाहन चालक मालक, सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र भारत टीम का अहम योगदान रहा।

गूंज लगातार रहा संपर्क में

चालक मालक सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र भारत टीम और दिनेश गेहलोत के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लगातार गूंज के पास आती रही और गूंज द्वारा उक्त जानकारी एसडीओपी पेटलावद, मजदूरों के परिजनों और मामले से जुड़े वकील को भेजकर मजदूरों के लोकेशन की जानकारी दी गई, मजदूरों के सःकुशल लौटने के बाद मजदूरों के परिजनों ने भी गूंज के प्रयासों की सराहना कर धन्यवाद दिया।

माफियाओं व अपराधियों को संरक्षण देकर थाना इंचार्ज रतनलाल परमार अपना जमीर बेच दिखा रहा है दबंगई

मामला: मारपीट व देसी कट्टे से धमकाने पर मामला दर्ज नहीं होने व सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लेने को धमकाने का

माही की गूंज, शुजालपुर। अजय राज केवट

जिस विभाग का रत्न अगर माफिआओं एवं अपराधियों को संरक्षण देकर अपना जमीर बेच अपनी दबंगई दिखाता हो तो, सहज ही यह स्पष्ट होता है कि, वह रत्न अपने साथ अपने आला अधिकारियों के साथ-साथ पूरे महकमे को ही कलंकित करने में कोई कसर नहीं झोडता है।

जी हां शाजापुर जिले के शुजालपुर मंडी थाने में पदस्थ एक रत्न थाना इंचार्ज एसआई रतनलाल परमार पदस्थ होकर अपनी ली गई ''देश भक्ति जनसेवा'' की शपथ को भूलकर गांधी छाप के मोह में इतना मुहा गया है कि, वह अपनी कर्तव्य निष्ठा को भूल अपने साथ अपने आला अधिकारियों की कार्य शैली को भी कलंकित कर पूरे महकमें की कार्य व्यवस्था को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

बतादें कि, मंडी थाना क्षेत्र में रहने वाले दबंग देवेंद्र पिता मेघराज जैन, दिव्यांग रामबाबू मीणा के कब्जे एवं मालिकाना हक की भूमि पर कब्जा करने की नियत से रामबाबू को हटाने के लिए मारपीट के साथ अवैध देसी कट्टे को कनपटी पर रख कब्जा नहीं हटाने पर जान से मारने तक की धमकी दे डाली। अवैध हत्यार देसी कट्टे से धमकाने एवं मारपीट करने वाले देवेंद्र जैन के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु मंडी थाना पर पीड़ित रामबाबू मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। परंतु शराब माफिआओं एवं सटोरियों को खुलेआम संरक्षण देने वाला थाना इंचार्ज के रूप में पदस्थ एक रत्न रतनलाल परमार दबंग एवं अवैध हत्यार रख मारपीट करने एवं धमकाने वाले दबंग देवेंद्र जैन के साथ सांठ-गांठ कर पीड़ित को ही धमका रहा है, इसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज नहीं होने पर मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की।

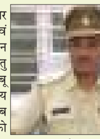

एसआई रतनलाल परमार

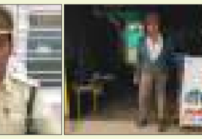

पिड़ित दिव्यांग रामबाबू मिणा।

एसआई रतनलाल, सीएम हेल्पलाइन से शिकायत लेने हेतु पीड़ित की दुकान पर पहुंचा धमकाने

माही की गूंज ने उक्त मामले को 17 दिसम्बर के अंक में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसके बाद पूरे मामले में रतनलाल की कथनी व करनी सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और मामले को रफा-दफा करने के लिए थाना इंचार्ज रतनलाल परमार अपने स्टाफ के साथ अपनी दबंगई पीड़ित दिव्यांग पर दिखाने हेतु उसकी दुकान पर जाकर सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत को वापस लेने हेतु धमकाया गया। इतना ही नहीं परमार ने अपनी दबंगई दिखाते हुए कानून को अपने बाप की बपोती मान पीड़ित दिव्यांग रामबाबू मीणा को सीएम हेल्पलाइन से शिकायत नहीं लेने पर उसके विरुद्ध ही मामला दर्ज कर देने की धमकी पीड़ित को दी गई, जिसका वीडियो भी माही की गूंज के पास उपलब्ध है।

अपने स्टाफ के साथ परमार पहुंचा पिड़ित को धमकाने।

एसपी साहब आपका यह अधिकारी और क्या ऐसा कार्य करेगा, तब आप ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ? जो आपके साथ पूरे पुलिस महकमें को कलंकित कर रहा है। अगर एसपी साहब आप यह बात जिले की जनता को बता दें तो शायद पता चल जाए कि, आपके अधिनस्थ अधिकारी किस निचले स्तर तक जाकर कार्य करेंगे जिसके बाद ही आप अपने ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्रवाई करेंगे !

धरना खत्म, भूख हड़ताल की तैयारियां शुरू, पत्रकारों का प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप, कलेक्टर भी दबे राजनीतिक दबाव में

माही की गूंज, थांदला।

बीते 10 दिनों से फालना नगर के पत्रकार समिति द्वारा धरना दिया जा रहा था, मामला नगर परिषद की दुकान नीलामी व पोस्ट ऑफिस की जमीन को गलत तरीके से बेचने का आरोप था। धरने पर बैठे नगर पत्रकार समिति ने मामले की जांच और दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए की मांग रखी। शासन की भूमि को सत्ता धारी ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। वही सरकारी नाले पर बनी दुकानों का निर्माण बंद कर हटाने के आदेश तहसीलदार ने दिया था, लेकिन आदेश के बाद भी मामले को भ्रष्टाचार की भेट चढाने के लिए आदेश को ताक में रख दिया। कलेक्टर रोहित सिंह का कहना है कि, जो पत्रकारों की मांग है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है कहकर अपने कार्य की इतिश्री कर दी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422